Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज
Published from Ranchi
Ranchi ● Wednesday, 07 August 2024 ● Year : 02 ● Issue : 200 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com E-Paper : epaper.thephotonnews.com

सुविचार

व्यंग्य सत्य की खोज नहीं, झूठ की खोज है। यही उसका पेंचदार रास्ता है। झूठ की खोज के सहारे या उसके बहाने ही यहां सत्य को पहचानने की प्रक्रिया चलती है।

– श्रीलाल शुक्ल

Kriti Sanon Wishes Kajol Happy...

SHARE

सेंसेक्स	:	78,593.07
निफ्टी	:	23,992.55

SARAFA

सोना	:	6,560
चांदी	:	87.05

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

पुरुष भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा

NEW DELHI : मंगलवार को पेरिस ओलिंपिक में गत चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा ने ग्रुप बी क्वालीफिकेशन में अपने पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर के थ्रो के साथ पुरुष भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई लेकिन किशोर जेना बाहर हो गए। ग्रुप बी क्वालीफिकेशन में सबसे पहले थ्रो करने उतरे नीरज ने 89.34 मीटर से सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए आठ अगस्त को होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। नीरज ने ग्रुप ए और बी दोनों में शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया। ग्रुप बी से ग्रेनाडा के पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स (88.63 मीटर), राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम (86.59 मीटर), ब्राजील के लुईस मॉरीसियो डा सिल्वा (85.91 मीटर) और मालदोवा के एंड्रियन मारडेयर (84.13 मीटर) ने भी भाले को 84 मीटर से अधिक दूर फेंककर सीधे फाइनल में जगह बनाई।

आज कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश

RANCHI : मौसम विभाग की ओर से बुधवार को झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात की भी आशंका है। राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर की भी बारिश हो सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र की मानें तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा के अलावा पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। रांची की बात करें तो राजधानी के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना हैं। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है।

गिरावट जारी, फिर 166 अंक फिसला सेंसेक्स

NEW DELHI : मंगलवार को सेंसेक्स 166 पॉइंट (0.21 प्रतिशत) गिरकर 78,593 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के ऊपरी स्तर से इसमें 1259 अंकों की गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी 63 पॉइंट (0.26 प्रतिशत) गिरकर 23,992 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में सबसे ज्यादा निफ्टी रियल्टी 0.84 प्रतिशत चढ़ा। मेटल और आईटी इंडेक्स करीब आधा फीसदी चढ़े। सरकारी बैंक का इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.26 प्रतिशत गिरा। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी करीब आधा फीसदी गिरा। निफ्टी के 50 शेयरों में से 21 में तेजी और 29 में गिरावट रही। इस हफ्ते 900 से ज्यादा कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे आएंगे। आज टाटा पावर, टीवीएस मोटर्स, बाटा, रेमंड जैसी कंपनियां अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी हो रहे हैं।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में दिया बयान, ढाका में अधिकारियों से लगातार संपर्क

बांग्लादेश के बदलते हालात पर भारत की नजर, अभी इंडिया में रहेंगी शेख हसीना

AGENCY NEW DELHI : मंगलवार को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश के हालात पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में घटनाक्रम बदल रहा है। भारत अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रखे हुए है और ढाका में अधिकारियों के साथ भी नियमित संपर्क में हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी कुछ समय के लिए भारत में हैं। राज्यसभा में विदेश मंत्री ने एक विशेष बयान में बताया कि सरकार राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में हैं। वहां अनुमानित रूप से 19 हजार भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9 हजार छात्र हैं। उच्चायोग की सलाह पर अधिकतर छात्र जुलाई महीने में ही भारत लौट आए हैं।

सभी राजनीतिक दलों से साझा की गई चिंता

राजनयिक उपस्थिति के संदर्भ में विदेश मंत्री ने बताया कि ढाका में उच्चायोग के अलावा हमारे पास चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में सहायक उच्चायोग हैं। हमारी अपेक्षा है कि मेजबान सरकार इन प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक सुरक्षा संरक्षण प्रदान करेगी। स्थिति स्थिर होने पर हम उनके सामान्य कामकाज की आशा करते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हाल की हिंसा और अस्थिरता के बारे में चिंता सभी राजनीतिक दलों से साझा की गई है। जनवरी 2024 में चुनाव के बाद से बांग्लादेश की राजनीति में काफी तनाव, गहरा विभाजन और बढ़ता ध्रुवीकरण हुआ है। इस अंतर्निहित नींव ने इस वर्ष जून में शुरू हुए छात्र आंदोलन को उग्र कर दिया। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आंदोलन में कोई कमी नहीं आई। उसके बाद लिये गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों ने स्थिति को और खराब कर दिया। इस स्तर पर आंदोलन एक सूत्री एजेंडे पर केंद्रित था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना चाहिए।

- अल्पसंख्यकों और मंदिरों पर हुए हमले
- बीएसएफ ने बंगाल सरकार और सीमा क्षेत्र के निवासियों संग की मीटिंग
- बंगाल सीमा पर बढ़ा घुसपैठ का खतरा
- जल सीमा पर बीएसएफ ने तैनात किए स्पेशल निगरानी बोट
- फंसे सैकड़ों भारतीय लॉरी चालक-खलासी
- बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने ली अंतरिम सरकार बनाने की जिम्मेदारी
- पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम से लगी भारत और बांग्लादेश सीमा पर बढ़ाया गया अलर्ट

बांग्लादेश में हिंसा और संकट को लेकर संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक

राहुल ने पूछा- क्या बांग्लादेशी हिंसा में विदेशी हाथ है, जयशंकर बोले पाक डिप्लोमेट ने आंदोलन की तस्वीर लगाई थी, जुटा रहे जानकारी

बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र से पूछा कि क्या बांग्लादेश हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमैट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो में लगातार बांग्लादेश आंदोलन की तस्वीरें लगा रहे थे। इसलिए इस एंगल की जांच की जा रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर 2 महीने से जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच सोमवार को जमकर हिंसा हुई। इसके बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत आ गईं। वे अभी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में हैं। वे लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं।

संसद भंग, पूर्व पीएम खालिदा जिया रिहा

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी है। देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मंगलवार दोपहर 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी। इसके बाद वे पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंची थीं। हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजित डोभाल ने उनसे करीब एक घंटे बातचीत की थी।

प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या हुई 440

बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 440 हो गई। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से सोमवार को इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद हुई हिंसा की घटनाओं में 100 से ज्यादा की मौत हुई है। हिंसा प्रभावित देश में सेना स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। बीडीन्यूज24 डॉट कॉम समाचार पोर्टल ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ने के बावजूद मंगलवार को स्थिति सामान्य होने के संकेत मिले तथा पुलिस और सेना सड़कों पर गश्त कर रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सोमवार देर रात सभी राजनीतिक दलों से देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य करने में मदद करने का आग्रह किया।

पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में बनी सहमति

उम्रकैद की सजा काट रहे 30 कैदी होंगे रिहा

PHOTON NEWS RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन 67 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों पर पुनः विचार किया गया, जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली दो बैठकों में अस्वीकृत किए गए थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 67 कैदियों को कारामुक्त किए जाने के मामलों पर अधिकारियों के साथ गहन-विचार विमर्श किया। समीक्षा के क्रम में न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार विचार-विमर्श के उपरान्त 30 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी।

- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग
- 67 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों पर किया गया विचार-विमर्श

मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों की परेशानियों को जल्द करें दूर : मुख्यमंत्री

RANCHI : मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (जेएमएमएसवाई) में आ रहीं समस्याओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों, उपायुक्तों और सीएससी के वरीय पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने में लाभुक दीदी-बहनों को आ रही कठिनाइयों को जल्द से जल्द दूर करें, ताकि किसी भी जरूरतमंद को लाभ लेने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विभाग जल्द दिशा-निर्देश जारी करे। सर्वर डाउन रहने व अन्य तकनीकी कारणों से महिलाओं को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। वे निराश होकर बैरंग घर लौटने पर मजबूर हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए आयोजित विशेष शिविर में लाभुकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का हुजूम कैंप में उमड़ रहा है, लेकिन पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के कारण महिला लाभुक आवेदन नहीं कर पा रही हैं। इस कारण लाभुकों में निराशा देखी जा रही है। पूरे झारखंड से इस बाबत शिकायत मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया।

आरपीएफ के पूर्व डीआईजी संतोष दुबे को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

रेलवे बोर्ड की ओर से प्रीमैच्योर रिटायरमेंट दिए जाने के आदेश को अदालत ने किया निरस्त

PHOTON NEWS RANCHI : डीजी प्रिया दुबे के पति धनबाद के तत्कालीन सीनियर कमांडेंट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) संतोष कुमार दुबे के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने रेलवे बोर्ड द्वारा उन्हें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिए जाने के आदेश को निरस्त किया। साथ ही कोर्ट ने उनका जॉइनिंग अविलंब करने का आदेश रेलवे बोर्ड को दिया है। कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट से विभाग की कार्यवाही पर रोक के बावजूद रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रीमैच्योर रिटायरमेंट कर दिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। संतोष कुमार दुबे वर्तमान में डीआईजी आरपीएफ पद पर लखनऊ में पदस्थापित थे। दरअसल, संतोष कुमार दुबे के आरपीएफ में चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पदस्थापित रहने के दरमियान उन पर 1.48 करोड रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई ने दानापुर, पटना में 10 जुलाई 2013 को दर्ज किया था। इसके बाद आरपीएफ नई दिल्ली ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने के आदेश दिया था। सीबीआई ने संतोष कुमार दुबे के अधिकांश पोस्टिंग था जो झारखंड में थी, के दौरान उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। संतोष कुमार दुबे द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का चेक पीरियड 1998 से 2013 तक सीबीआई ने रखा है।

कोर्ट की विभागीय कार्रवाई पर रोक के बावजूद हुई थी कार्रवाई

2022 में दाखिल हुआ था आरोप पत्र

यह बता दें कि मामले में सीबीआई ने 28 जून 2022 को संतोष कुमार दुबे, उनकी पत्नी प्रिया दुबे एवं अन्य खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पटना ने 22 जुलाई 2022 को मामले में संज्ञान लिया था। 31 जनवरी 2023 को आरपीएफ, नई दिल्ली ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू किया था। इसके बाद संतोष कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में विभागीय कार्रवाई को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी। 5 अक्टूबर 2023 को झारखंड हाई कोर्ट ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ आरपीएफ द्वारा विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

केस फाइलिंग के नए नियम पर तीन जजों की बेंच का फैसला सुरक्षित

RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट में केस फाइल करने के नये नियम पर मंगलवार को पूर्ण पीठ ने सुनवाई की। इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस राजेश शंकर और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी बनाया था।

09 अगस्त को पीओपी का आयोजन, सूर्यास्त के बाद शुरू होगा समारोह

216 महिलाओं सहित नेवी को मिलेंगे 1390 अग्निवीर

AGENCY NEW DELHI : आईएनएस चिल्का पर ट्रेनिंग पूरा होने के बाद 1390 अग्निवीरों का चौथा बैच भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। इस बैच में 216 महिलाएं भी हैं, जिन्होंने एक साथ प्रशिक्षण पूरा किया है। इन अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड (पीओपी) 09 अगस्त को होगी, जिसका अवलोकन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी करेंगे। सूर्यास्त के बाद होने वाले इस समारोह में सभी अग्निवीर आईएनएस चिल्का के मुख्य द्वार से अंतिम पग लेंगे। इस अवसर पर नौसेना अग्निवीरों के साथ-साथ 330 तटरक्षक नाविक भी पास आउट होंगे।

आईएनएस चिल्का पर पासिंग आउट परेड की समीक्षा करेंगे नौसेना प्रमुख

दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर होंगे परेड के संचालन अधिकारी

- नौसेना अग्निवीरों के साथ 330 तटरक्षक नाविक भी होंगे पास आउट, खेल जगत की हस्तियां भी होंगी शामिल

काबिल अग्निवीर किए जाएंगे पुरस्कृत

आईएनएस चिल्का पर दिए गए प्रशिक्षण में शैक्षणिक, सेवा के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण और कर्तव्य, सम्मान एवं साहस के मूल मूल्यों पर आधारित आउटडोर प्रशिक्षण भी शामिल था। पीओपी के दौरान काबिल अग्निवीरों को नौसेना प्रमुख की ओर से विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। परेड के बाद नौसेना प्रमुख नई अवसंरचना के निर्माण, सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न प्रभागों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पीओपी का सीधा प्रसारण 09 अगस्त को सायं 05:10 बजे से भारतीय नौसेना के यू-ट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और दूरदर्शन के क्षेत्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास इस परेड के संचालन अधिकारी होंगे। ओडिशा में आईएनएस चिल्का पर होने वाले इस महत्वपूर्ण समारोह में पास आउट होने वाले अग्निवीरों के परिजन और जाने-माने दिग्गजों के साथ-साथ खेल जगत की हस्तियां भी शामिल हो सकेंगी। नौसेना की यह पीओपी न केवल अग्निवीरों के 16 सप्ताह के प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफल समापन का प्रतीक है।

पुलिस ने शुरू की सेना के कब्जे वाली जमीन से जुड़े केस की जांच

RANCHI : रांची पुलिस ने भी लैंड स्कैम केस की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम के आरोपी जेल में बंद अफसर अली को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने अफसर अली को उस केस में गिरफ्तार किया है, जो सेना की कब्जे वाली भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज है। अफसर अली की गिरफ़्तारी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए कोर्ट से दो दिनों की रिमांड देने का आग्रह किया है। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद रांची पुलिस अफसर अली से जेल में पूछताछ करेगी। अफसर अली फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम का सहयोगी है। ईडी ने पिछले वर्ष जब अफसर अली के ठिकाने पर छापेमारी की थी तब वहां से कई दस्तावेज और डीड भी बरामद हुए थे।

सीआईडी ने दो आरोपियों को दबोचा

बंगाल की पॉवर ऑफ अटॉर्नी से बेची जमीन

CRIME REPORTER RANCHI : बंगाल रजिस्ट्री कार्यालय से कराई गयी फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रांची में जमीन बेचने के मामले में सीआईडी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआईडी ने संतोष साहू और विकास साहू को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए सीआईडी के इन्स्पेक्टर शिव गोप ने बताया कि संतोष साहू और विकास साहू की क्या भूमिका है यह पता किया जा रहा है। अब तक इस केस में छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिस जमीन की बंगाल के पॉवर ऑफ अटॉर्नी को आधार बना कर खरीद-बिक्री की गयी है वह रांची के पिठोरिया इलाके के जमुआरी मौजा में स्थित है।

- अब तक इस केस में छह लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार

हजारीबाग की स्टील कंपनी में विस्फोट से एक कर्मचारी की मौत

पांच गंभीर, दोपहर 12 बजे तेज आवाज से मची अफरातफरी

PHOTON NEWS HAZARIBAG: जिले के बरही में पवनपुत्र स्टील एंड एलॉय प्लांट की चिमनी में मंगलवार को हुए जोरदार ब्लास्ट में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल हजारीबाग शहर के आरोग्यम अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने चार को रांची के लिए रेफर कर दिया।

अस्पताल में इलाजरत कर्मचारी व घटनास्थल पर जांच करतीं उपविकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ● फोटोन न्यूज

जानकारी के अनुसार प्लांट की चिमनी में दोपहर करीब 12 बजे धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि वहां काम कर रहे मजदूर हवा में दूर तक उछल गए। सभी 80 से 90 फीसदी झुलस गए थे।

एक मजदूर जितेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। रेफर किए गए घायलों में राजू, राजेश, शैलेश और रामदेव हैं। एक मजदूर नरेंद्र कुमार का इलाज आरोग्यम अस्पताल में चल रहा है। बरही में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जियाडा) की ओर से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। अस्पताल में मजदूरों का स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव भी पहुंचे। इधर, ब्लास्ट की वजह से फैक्टरी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके बारे में फिलहाल प्लांट की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। घटना के बाद उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित बरही घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची।

टाटा कंपनी के कर्मचारी के घर चोरी करने वाला चोर हुआ गिरफ्तार

RAMGARH : जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में टाटा कंपनी के कर्मचारी के घर में चोरी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की जानकारी मंगलवार को रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि पांच अगस्त को सूचना मिली थी कि टाटा कंपनी के कर्मचारी महताब आलम के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा रात्री में ताला तोड़कर क्वार्टर से लाखो रुपया का सामान की चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में अज्ञात चोर के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के निदेर्शानुसार कांड का सफल उद्भेदन एवं चोरी गयी सामान की बरामदगी के लिए टीम गठित कर छापेमारी शुरू की गई। इस दौरान अभियुक्त राजू रजक पिता जालो रजक ईसीसी कॉलोनी पानी टंकी घांटोटांड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर कांड में चोरी गयी सभी समान और जेवर को बरामद किया गया।

तीन हजार लीटर अवैध कास्टिक सोडा के साथ कारोबारी गिरफ्तार

लाइन होटल के पास होता था अवैध धंधा, आरोपी बंगाल का

PHOTON NEWS PALAMU : जिले की एक मात्र कास्टिक सोडा फैक्ट्री के चालक के गलत कारनामे उजागर हुए हैं। चालक फैक्ट्री से टैंकर लेकर निकलने के बाद रास्ते में गाड़ी रोककर कैमिकल बेच देता था। सतबरवा पुलिस की कार्रवाई में चालक की करतूत सामने आयी है। इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्दमान जिले के दुगार्पुर के रहने वाले कास्टिक सोडा कारोबारी मुकुल मंडल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह जानकारी मंगलवार को दी। पुलिस ने कारोबारी के पास से तीन हजार लीटर कास्टिक सोडा बरामद किया है, जो 15 ड्राम में भरा पड़ा था। नीले रंग के 16 खाली ड्रम, 2000 लीटर सिंटेक्स की तीन पानी टंकी के अलावा मोटर पंप और ड्रम बंद करने वाले 60 पीस कैप व एक आसमानी

आरोपी के साथ पुलिस जवान

कलर का आईक्यू मोबाइल सेट जब्त किया गया है। सतबरवा के थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कास्टिक सोडा के अवैध कारोबार करने के आरोपी को करीब 3000 लीटर कास्टिक सोडा के साथ गिरफ्तार किया गया। महेंद्र लाइन होटल के समीप भारत भूषण जायसवाल के गोदाम में अवैध कारोबार होता था। छापामारी के दौरान पकड़ा गया आरोपी मुकुल मंडल मौके से भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर कास्टिक सोडा से संबंधित कागजात आरोपी प्रस्तुत नहीं कर सका। उसने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि रेहला कास्टिक सोडा फैक्ट्री में कार्यरत चालक से उसकी सांठगांठ है। गोदाम में आकर वह माल टैंकर से उतार देता है, उसके बाद टैंकर में पानी भर दिया जाता था। थाना प्रभारी के अनुसार उक्त कास्टिक सोडा का जाली कागजात आसनसोल से बनवाकर बेचा जाता था। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी कास्टिक सोडा के धंधे में पकड़े जाने पर मुकुल मंडल जेल जा चुका है। थाना प्रभारी के अनुसार बीएनएस थाना कांड संख्या 95/24 धारा 317 (2) के तहत कार्रवाई की गई है।

कोल्हान आवासीय विद्यालय की समस्याओं को लेकर सौंपा मांगपत्र

CHAKRADHARPUR : कोल्हान आवासीय विद्यालय के छात्रों ने छात्रावास तथा वार्डन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को मांगपत्र सौंपा। इसमें कहा गया है कि कोल्हान आवासीय विद्यालय मोजोडिम्बा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान चैनपुर चक्रधरपुर में 2016 से संचालित हो रहा है। विद्यालय भवन तथा छात्रावास पूरी तरह अभावों से जूझ रहा है। इसके साथ ही वार्डन 3 सालों से प्रतिनियोजित हैं तथा उनके होने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वार्डन अमूल्य चंद्र प्रधान रात्रि विश्राम छात्रावास में नहीं करते हैं। विद्यालय तथा छात्रावास में अभावों के कारण पठन-पाठन तथा दैनिक जीवन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रावास के शौचालय के दरवाजे टूट गए हैं। लाइट नहीं हैं। नल और बाल्टी तक नहीं है। छात्रावास में भोजन मनमुताबिक मिलता है। मेनू चार्ट कभी नहीं दिखाया जाता। भोजन की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हरी सब्जी और रोटी नहीं मिलती। सुबह में गुड़-चना कई दिनों से बंद है। स्वच्छ जल का अभाव है। बिजली जाने पर कभी जेनरेटर नहीं चलाया जाता है। हम अंधेरे में रहते हैं। बिजली नहीं होने से पठन-पाठन तथा भोजन टॉर्च की सहायता से करते हैं। स्वास्थ्य खराब होने पर रात्रि में वाहन की व्यवस्था नहीं रहती है। तीन सालों से हाउस ड्रेस तथा ट्रैकसूट नहीं मिला है। इस सत्र में स्कूल ड्रेस भी नहीं मिला है। पत्र की प्रतिलिपि आयुक्त, उपायुक्त, निदेशक जेसीईआरटी, अनुमंडल पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कोल्हान को भी प्रेषित की गई है।

लोहरदगा में आटा चक्की फटने से एक की मौत, दो बच्चे घायल

LOHARDAGA : जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र अन्तर्गत सेन्हा जंगल मुहल्ला के समीप आटा चक्की ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हो गई जबकि दो बच्चे गम्भीर रूप से घायल हो गये। दोनों घायल बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार सेन्हा जंगल मुहल्ला निवासी 21 वर्षीय असफाक अंसारी घर पर मंगलवार को आटा पिसाई कर रहा था। इस दौरान चक्की ब्लास्ट कर गया, जिससे वह घायल हो गया।

साथ ही वहां खड़े 6 वर्षीय तंजील अंसारी और 3 वर्षीय साकिब अंसारी भी गम्भीर रूप से घायल हो गये। तीनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेन्हा

अस्पताल में मौजूद परिजन

ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के पश्चात सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया गया। अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही असफाक अंसारी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सेन्हा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की।

गिरिडीह में मामूली बात पर दो पक्षों में मारपीट, 12 घायल

GIRIDIH : जिले के पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत जगमनरायडीह गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प में 12 लोग घायल हो गये। घटना सोमवार देर रात की है। बताया गया कि देर रात कुछ लोग ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे। इस दौरान आम के पेड़ की डाली टूट गई। इसको लेकर पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। फिर जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 12 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी को देर रात सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में मुस्लिम मियां, ताहिर मियां, बदरुद्दीन मियां, कमरुद्दीन मियां, सलाउद्दीन मियां, मिनहाज मियां, नियाकत मियां, लियाकत मियां, सलमान मियां, साबिर मियां और मेहरुनिशा, मोहम्मद नासिर अंसारी और मंजूर अंसारी में शामिल हैं। घटना को लेकर दोनों पक्ष की ओर से पचंबा थाना में आवेदन दिया गया है।

खेत देखने जा रहे पिता-पुत्र को लगा बिजली का करंट, मौत

खेत में पहले से गिरा था तार, अस्पताल ले जाने के क्रम में तोड़ा दम

PALAMU : जिले के पांकी थाना क्षेत्र के हुरलौंग गांव में मंगलवार सुबह दर्दनाक घटना हुई। खेत देखने जाने के क्रम में बिजली के करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से पिता- पुत्र की मौत हो गई। मृतकों में हुरलौंग गांव के निवासी नागेंद्र चंद्रवंशी (55) और उनके पुत्र अश्विन वर्मा उर्फ पिंटू चंद्रवंशी (30) शामिल हैं। अश्विन वर्मा उर्फ पिंटू चंद्रवंशी रोजगार सेवक बताए गए हैं। जिले के पिपरा की हरैया पंचायत में कार्यरत थे। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह दोनों पिता पुत्र अपने खेत देखने जा रहे थे। इसी दौरान, बिजली तार की चपेट में आकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन और स्थानीय

अस्पताल में जुटे लोग ● फोटोन न्यूज

ग्रामीण तुरंत उन्हें पांकी के हुरलौंग स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए, जहां स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। बाद में उन्हें इलाज मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत पाया। चर्चा है कि घटनास्थल पर ही पिता की मौत हो गई थी, जबकि पुत्र की इलाज के लिए लाने के दौरान मौत हुई। परिजन वीरेंद्र चंद्रवंशी ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है। बिजली का तार टूट कर गिरा हुआ था। पहले पिता को करंट लगा। बचाने के दौरान पुत्र भी चपेट में आ गया। दोनों का हाथ और सीने का हिस्सा जला है।

गिरिडीह की उसरी नदी में डूबे युवक का शव बरामद

GIRIDIH : बाबा दुखहरण नाथ मंदिर के पास उसरी नदी में डूबे युवक का शव 24 घंटे बाद मंगलवार की दोपहर बरामद कर लिया गया। धनबाद जिले के सिजुआ न्यू श्याम कॉलोनी निवासी युवक गौतम चौहान सोमवार को नदी में नहाने के दौरान में नदी की धारा में बह गया था। घटना के बाद स्थानीय युवकों के काफी प्रयास के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला था।

मालूम हो कि गौतम अपने परिवार के साथ तीसरी सोमवार पर बाबा दुखहरण नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना आया था। पूजा से पहले वह नदी में स्नान करने के दौरान वह डूब गया था। मंगलवार को धनबाद के गोताखोरों की टीम नदी तट पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव बरामद कर लिया।

अनुसूचित जनजाति के लोगों का किया जाए समुचित संवर्द्धन : लकड़ा

SARAIKELA : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों व सभी विभागों के योजनाओं में प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त रविशंकर शुक्ला व पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत भी मौजूद रहे। सदस्य ने सभी विभाग अंतर्गत संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार के योजनाओं में प्रगति की समीक्षा तथा योजनाओं में अनुसूचित जनजाति की भागीदारी से संबंधित चर्चा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अनुसूचित जनजातियों को शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने के साथ हर दृष्टिकोण से उनका संवर्द्धन भी करना है।

गिरिडीह में छिनतई कर भाग रहे अपराधी को लोगों ने दबोचा

अपराधी को पकड़ कर ले जाते ग्रामीण

GIRIDIH : गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र स्थित चतरो बजार में मंगलवार को झपटमार ने रुपये का झोला तो झपट लिया लेकिन लोगों की सक्रियता से पकड़ लिया गया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया से देवरी थाना क्षेत्र के करमाटांड़ लछुवाडीह गांव निवासी सह सेवानिवृत्त चौकीदार जॉन मरांडी ने पैसे निकाले थे। पैसे निकालने के बाद उसे झोले में रखकर वह बैंक से बाहर निकले। 10 हजार रुपये जेब में रखा, जबकि झोले में 50 हजार रुपये रखा। वह पैदल जा रहे थे कि उसी दौरान एक झपटमार ने उनका झोला झपट लिया और भागने लगा। जब जॉन ने चिल्लाया तो लोग जुटे और अपराधी के पीछे भागे। लोगों ने थोड़ी ही दूर पर उसे दबोच लिया। पकड़ा गया अपराधी अंतरराज्यीय चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। वह बिहार के मोतिहारी जिला का रहने वाला है।

कोडरमा में संदिग्ध अवस्था में मिला विवाहिता का शव, पति हिरासत में

KODERMA : जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रायडीह में मंगलवार को संदिग्ध अवस्था में पंखे से लटकता विवाहिता का शव मिला। मृतका की पहचान पूर्णिमा देवी (19) के रूप मे हुई है। जानकारी के अनुसार विवाहिता पूर्णिमा 5 महीने की गर्भवती थी। पूर्णिमा की शादी फरवरी में हुई थी, जिसका मायका तिलैया के विद्यापुरी में है। मृतिका के पति रोहित सोनकर ने कहा कि वह पटना में काम करता है। वहां जाने के लिए उसकी पत्नी जिद कर रही थी लेकिन वह इंकार कर रहा था। इस बीच वह घर से बाहर गया और लौटा तो देखा कि उसका कमरा अंदर से बंद था। हो-हल्ला करने के बाद गेट तोड़ा गया तो देखा कि उसकी पत्नी पंखे से साड़ी के सहारे फंदे पर लटक रही थी।

मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय के मेधावी छात्र हुए सम्मानित

बड़ा इंसान बनने के लिए विद्यार्थी मेहनत करें, सफलता कदम चूमेगी : विधायक

CHAKRADHARPUR : मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय सभागार में मंगलवार को मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा में बेहतर अंक से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसमें मैट्रिक बोर्ड के टॉपर स्नेहा महतो, मोहित कुमार महतो व मौसमी चटर्जी एवं इंटरमीडिएट के विज्ञान संकाय में सत्यजीत साहू, जसवंत महतो, शिवम महतो व सुजल सोनकर, कला संकाय में रितिक रोशन महतो, कोलाई सामड, दिव्यांशु सिजुई व वाणिज्य संकाय में सरिया नाज, मोनिका कुमारी, मोहित कुमार मिस्त्री को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक सुखराम उरांव ने कहा

छात्रा को सम्मानित करते विधायक सुखराम उरांव ● फोटोन न्यूज

कि इंसान का कद या पद से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि बड़ा इंसान बनने के लिए विद्यार्थी लगन के साथ मेहनत करें, निश्चित सफलता कदम चूमेगी। तत्पश्चात स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रभारी प्राचार्य सोसन प्रभावती खेस, सहायक शिक्षक हेमंत कुमार पान, दिब्या प्रधान, पंकज प्रधान, प्रीति पाठक, लक्ष्मी टुटी, ज्योति ललिता जामुदा, पुनता माझियान, मंजू कुमारी, सुषमा डहांगा, प्रेम चंद महतो,विजय तैसुम, ममता पुर्ती आदि शिक्षक-शिक्षिका सक्रिय रहे।

धनबाद परिसदन में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) एवं सहायक निवार्ची पदाधिकारी (एईआरओ) के साथ की बैठक

फार्म रिजेक्ट करने से पहले सत्यापन अवश्य करें, वैध कारण पर ही रद्द करें

● प्रमंडलीय आयुक्त ने धनबाद जिला के विभिन्न मतदान केंद्रों का लिया जायजा, दिया जरूरी दिशा-निर्देश

PHOTON NEWS HAZARIBAG: प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग सुमन कैथरीन किस्पोट्टा मंगलवार को धनबाद जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने धनबाद परिसदन में मतदाता सूची द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसएसआर) 2024 के प्रगति कार्य की सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने विधानसभावार धनबाद, झरिया, सिंदरी, टुंडी, बाघमारा, निरसा में पुनरीक्षण कार्यक्रम द्वारा जोड़े गए नए मतदाताओं, वरिष्ठ

अधिकारियों व कर्मचारियों से जानकारी लेतीं प्रमंडलीय आयुक्त

विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

बैठक के उपरांत प्रमंडलीय आयुक्त कैथरीन किस्पोट्टा ने धनबाद एवं झरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) का जायजा लिया। उन्होंने झरिया के बूथ नंबर 22, 23, 24, 25, 178, 192, 194, 213, 214, 215, 216 एवं धनबाद विधानसभा क्षेत्र के 240,241, 242, 243, 244, 249 एवं 250 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं, मृत मतदाताओं के नाम विलोपित करने आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग ने प्राप्त फार्म 06, फार्म 07 एवं फार्म 08 और निष्पादित फार्मों व रिजेक्टेड फार्मों के संबंध में सभी संबंधित ईआरओ से जानकारी प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभावार रिजेक्शन फार्मों के कारणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि फार्म रिजेक्शन का सत्यापन अवश्य करें, वैध कारण पर ही फार्म को रद्द करें। वहीं लंबित फार्मों का निष्पादन सुनवाई करते हुए समाप्त करने का निर्देश दिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी ईआरओ-एईआरओ को अपने-अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का नियमित भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतदान केंद्रों की जानकारी किसी को नहीं हो। उन्होंने बूथ लेवल आफिसर के साथ नियमित बैठक करने एवं कार्य प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर समय निर्धारित है। अतः सभी कार्यों का निष्पादन समयबद्ध होना है। इसे सभी ईआरओ-एईआरओ सुनिश्चित करेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त ने कम वोटिंग वाले मतदान केंद्रों की भी समीक्षा कर संबंधित मतदान केंद्र के मतदाता सूची को दुरूस्त करने, मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने, हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान स्टीकर चस्पा करने को लेकर समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सभी क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्री-मैट्रिक छात्रवृति का पोर्टल पर ही होगा आवेदन व सत्यापन

HAZARIBAG : प्री-मैट्रिक छात्रवृति के अंतर्गत ई-कल्याण पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने या स्वीकृति आदि में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को समाहरणालय सभागार में एकदिवसीय जिलास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का संचालन जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण कुमार हजारीबाग की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में प्रत्येक प्रखंड के 4 व्यक्ति, जिसमें 2 आईएनओ एवं 2 बीआरपी शामिल हुए। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृति के लिए 1-10 तक के वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के छात्रवृति के लिए संबंधित विद्यालय के आईएनओ द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन सत्यापन भी किया जाना है। ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान छात्र-छात्राओं का बैंक खाता एवं आईएफएससी कोड सही से इंट्री किया जाना है। वर्ग 1-8 तक के जिन छात्र-छात्राओं का बैंक खाता नहीं है, उनके माता-पिता/अभिभावक का बैंक खाता दिया जा सकता है। वर्ग 9-10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का आधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है।

लोहरदगा में पल्स पोलियो अभियान की तैयारी शुरू

समाहरणालय में बैठक करते उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण

LOHARDAGA : उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में पल्स पोलियो कार्यक्रम (25 अगस्त) को लेकर मंगलवार को जिला टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में हुई। बैठक में पल्स पोलियो कार्यक्रम को सफल बनाने, पल्स पोलियो कार्यक्रम के दौरान आने वाले बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के सर्वेक्षण और डेटा प्रबंधक को इससे संबंधित डेटा संग्रह और एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। इससे पूर्व उपायुक्त ने प्रखण्डों में पूर्ण टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की और उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया। साथ ही निर्देश दिया कि इस माह टीकाकरण का कार्य सभी प्रखण्डों में सौ प्रतिशत कर लिया जाए। आवश्यकता पड़ने पर शिविर लगाया जाए। प्रखण्ड स्तर पर कर्मियों की कमी रहने पर जिला मुख्यालय से टीम भेज कर कार्य संपन्न कराया जाए। टीकाकरण कार्यक्रम में जन्म के समय दिया जाने वाला टीका, बीसीजी, पेंटा-1, पेंटा-3, मिजल्स व एमआर का पहला डोज, एफआई और मिजल्स एमआर का दूसरा डोज शामिल है।

BRIEF NEWS

रिक्त पदों में एससी को उचित स्थान देने की हेमंत से मांग

RANCHI : गिरिडीह के बिरनी के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार ने रिक्त पदों में अनुसूचित जाति वर्ग को उचित स्थान देने का अनुरोध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। उनका कहना है कि राज्य में सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में एससी समुदाय वर्ग को चौकीदार बहाली में सभी जिलों में सीटो की संख्या शून्य कर दी गई, जबकि झारखंड राज्य में वर्तमान समय में एससी समुदाय की आबादी लगभग 15 से 20 प्रतिशत है।सीपीडीओ विज्ञापन में मात्र दो सीट और वर्तमान समय में वन क्षेत्र पदाधिकारी विज्ञापन में एससी समुदाय वर्ग को मात्र एक सीट दी गई है, जबकि आरक्षण रोस्टर के अनुसार 17 सीट होना चाहिए। इसलिए हमलोग की सरकार से मांग है कि चौकीदार विज्ञापन और वन क्षेत्र पदाधिकारी विज्ञापन में एससी सीटो में वृद्धि के साथ पुनः विज्ञापन जारी किया जाए और आरक्षण रोस्टर का पालन किया हो।

सूर्य मंदिर में भगवान शिव का किया गया श्रृंगार

RANCHI : श्रावण मास के अवसर पर रांची देवी मंडप रोड हेसल सरोवरनगर स्थित सूर्य मंदिर में भगवान शिव जी का श्रृंगार कर पूजा अर्चना कर शिव चालीसा,महामृत्युंजय मंत्र,गायत्री मंत्र,संध्या पाठ भजन कर आरती किया गया। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर शिव शंकर पाठक,मनोज कुमार पुटू,मुन्ना कुमार,अमित पाठक,शकुंतला दुबे,मीरा देवी,सुनैना देवी,अर्चना मिश्रा, सुनीता देवी,आशा मिश्रा,नीतू सिंह एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

'एक मुलाकात, अपनों के साथ' अभियान शुरू

RANCHI : प्रदेश कांग्रेस का 'एक मुलाकात, अपनों के साथ' अभियान मंगलवार से शुरू हो गया। कार्यक्रम के तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रांची महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कांके शहरी प्रखंड, मोराबादी प्रखंड, रातू रोड उत्तर प्रखंड, रातू रोड दक्षिण प्रखंड, किशोरगंज, हिदपीढ़ी, अरगोड़ा, हिनू प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, कार्यकताओं तथा कांग्रेसजनों से मुलाकात की और संगठन तथा सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाओं की विस्तार से चर्चा की। सबसे पहले वे कांके शहरी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल उरांव से उनके आवास में मिले। इसके बाद मोराबादी प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विक्की करमाली के आवास में कांग्रेसजनों से मुलाकात की।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 26-27 अगस्त को

RANCHI : श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति के तत्वावधान में 26 और 27 अगस्त को अलबर्ट एक्का चौक के पास जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जायेगा। समिति के संरक्षक सह रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, अजय मारु व समिति अध्यक्ष मुकेश काबरा ने बताया कि महोत्सव धूमधाम से मनाया जायेगा।दही हांडी प्रतियोगिता में पुरुष गोविंदा टीम व महिला गोविंदा टीम हिस्सा लेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बाल गोपाल और दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मेन रोड स्थित केडिया साइकिल व स्टेशन रोड स्थित पतंजलि बाबा रामदेव के सेंटर में संपर्क किया जा सकता है।

जेपी पटेल के दल-बदल मामले में मांगा जवाब, 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को हाईकोर्ट का नोटिस

PHOTON NEWS RANCHI : दलबदल के मामले में जयप्रकाश भाई पटेल की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जयप्रकाश भाई पटेल की सदस्यता रद्द करने संबंधी फाइल एवं प्रोसीडिंग्स का दस्तावेज मांगा है। इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्हें बिना सुने हुए और बिना अवसर प्रदान किए हुए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष के पास अन्य सदस्यों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी कई मामले अभी लंबित है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 अगस्त निर्धारित की है। दरअसल, विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण ने जयप्रकाश भाई पटेल के खिलाफ इस संबंध में दायर शिकायत पर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सुनवाई के बाद उनकी विधानसभा सदस्य को रद्द करने का फैसला सुनाया था, यह फैसला 26 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। मांडू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश भाई पटेल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके टिकट पर हजारीबाग सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे।

अदालत ने जताई कड़ी नाराजगी, यातायात एसपी कोर्ट में हुए हाजिर

लगातार आदेश के बाद भी नहीं सुधर रही ट्रैफिक व्यवस्था, लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं

RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी पर नाराजगी जताते हुए मौखिक कहा कि कोर्ट के कई आदेश के बावजूद भी राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत है। 7 वर्षों से यह जनहित याचिका चल रही है लेकिन रांची में जाम की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। कोर्ट ने अवैध ढंग से चल रहे ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान ट्रैफिक एसपी कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। कोर्ट ने उनसे सड़क के विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक पोस्ट एवं उसमें वॉशरूम की व्यवस्था के संबंध में जानना चाहा। इस पर ट्रैफिक एसपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रांची में 60 ट्रैफिक बूथ एवं 50 ट्रैफिक पोस्ट चिन्हित किया गया है। रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि ट्रैफिक बूथ और पोस्ट के निकट मॉड्यूलर वॉशरूम की व्यवस्था कर दी जाएगी। कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी से मौखिक कहा कि रांची में ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा चालको का ड्रेस कोड लगातार मेंटेन रहे यह सुनिश्चित करें। ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनी रहे इसके लिए लगातार स्पेशल अभियान चलाएं। यह भी देखें की ऑटो या ई रिक्शा चालक अपने वाहन में निर्धारित संख्या से ज्यादा यात्री किसी भी स्थिति में ना बैठाए। राजधानी रांची में ट्रैफिक में सुधार जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। वीआईपी मूवमेंट के समय तो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहती है लेकिन आम लोगों का रांची के सड़कों पर चलना काफी कष्टकारी होता है। प्रतिदिन उन्हें जाम की समस्या से निपटना पड़ता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रैफिक सुधार के लिए किए गए उपायों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त निर्धारित किया। रांची में ट्रैफिक की व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई।

मुख्य सचिव व राज्यपाल के प्रधान सचिव संजय के आवेदन को चार सप्ताह में करें निष्पादित : हाईकोर्ट

RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट ने राज्यपाल के प्रधान सचिव और मुख्य सचिव को पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के भाई संजय कुमार की सजा कम कर रिहा करने के आवेदन को चार सप्ताह में निष्पादित करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में संजय राय की ओर से सजा कम कर रिहा करने को लेकर दायर याचिका कीमंगलवारको सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता संजय कुमार राय को मुख्य सचिव एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव के पास सजा कम करने एवं रिहा करने का फ्रेश आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राजपाल के प्रधान सचिव एवं मुख्य सचिव को इस आवेदन का निष्पादन कर सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। कोर्ट को सुनवाई के द्वारा बताया गया कि सजा कम करने एवं रिहा करने से संबंधित प्रार्थी का आवेदन राज्यपाल के प्रधान सचिव एवं मुख्य सचिव के पास अब तक लंबित पड़ा हुआ है। कोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दिसंबर 2016 में 1.46 करोड़ के आय से अधिक संपति के मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी व भाई संजय कुमार को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी। हरिनारायण राय 2005 से 2009 तक विधायक व मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। पहले इस मामले की जांच झारखंड की निगरानी ब्यूरो कर रही थी। वर्ष 2010 में सीबीआई ने इस केस को टेकओवर किया था।

अवैध हथियार रखने के दोषियों को 7 साल कैद

RANCHI : रांची सिविल कोर्ट ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार क्यूम अंसारी और निजाउल अंसारी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने मंगलवार को दोषियों पर 13 हजार रुपये जुमार्ना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुमार्ने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त नौ महीने जेल काटनी होगी। पहला दोषी क्यूम अंसारी नगड़ी थाना क्षेत्र के बरसा गांव निवासी और निजाउल अंसारी लोहरदगा के कुडू थाना के जोनरो गांव निवासी है। दोनों को पुलिस ने सात सितंबर, 2018 को लोडेड देशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ नगड़ी थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 139/18) दर्ज कराई थी।

ऐसे सफेदपोश राष्ट्र के विकास में हैं बाधक : अदालत

781 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट ने फर्जी फर्मों और चालान से जुड़े 781।39 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी मामले में आरोपी सुमित गुप्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि देश का एक साधारण व्यक्ति भी राष्ट्र व राज्य के निर्माण और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान कर रहा है। लेकिन आरोपी सुमित गुप्ता जैसे व्यक्ति जो सफेदपोश अपराधी हैं, वे फर्जी कागज और फर्म बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जालसाजी करके और व्यक्तिगत लाभ गिद्ध दृष्टि रखकर सार्वजनिक धन की हानि करके राष्ट्र और राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र और राज्य के विकास में बाधा आ रही है। समाज के ऐसे सफेदपोश अपराधियों को आंख खोलने वाला संदेश भेजने के लिए अलग दृष्टिकोण से निपटा जाना चाहिए। आरोपी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुमित गुप्ता पर जमशेदपुर में जीएसटी चोरी का मामला दर्ज है। सेंट्रल जीएसटी विभाग की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीएस पति और अनुराग विजय ने पक्ष रखा। वहीं सुमित गुप्ता की ओर से अधिवक्ता नितिन कुमार पसारी ने बहस की।

हत्या करने की रची गई थी आपराधिक साजिश, एक अरेस्ट

जमीन विवाद में राजेश को मारी थी गोली

CRIME REPORTER RANCHI : कांके थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास एक अगस्त को राजेश मुंडा को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। इस घटना में शामिल सौरभ कुमार सिंह नाम के एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बतलाया कि वह चन्दवे बस्ती के राम पाहन, जो जमीन दलाली का काम करता है, उसके साथ लोगों को धमकाने का काम किया करता है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजेश मुण्डा का राम पाहन के साथ फोरलेन सड़क में अधिग्रहण की जाने वाली जमीन, अंचल कार्यालय में जमीन के दस्तावेजीकरण और मुआवजा को लेकर जमीनी विवाद था। राम पाहन के कहने पर ही जमीनी विवाद को लेकर राजेश मुण्डा की हत्या करने का आपराधिक षडयंत्र रचा गया था। राम पाहन पूर्व में हत्याकांड शामिल रहा है। गिरफ्तार आरोपित मूल रूप से बिहार के गोपालगंज का रहने वाला है। वर्तमान में वो गोन्दा थाना क्षेत्र के पतराटोली में रहता है। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किया।

गिरफ्तार अपराधी के बारे में जानकारी देते रांची एसएसपी चंदन कुमार।

नई दिल्ली को 7-0 से हराकर झारखंड की बेटियों ने दिखाया दम

RANCHI : दिल्ली के तेजस फुटबॉल मैदान में जारी 63वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर 17 बालिका टीम ने दमदार जीत के साथ शुरूआत की है। झारखंड की अंडर 17 बालिका टीम ने अपने पहले ही मुकाबले में नयी दिल्ली को 7-0 के अंतर से बड़ी शिकस्त दी है। इस मुकाबले में बबिता कुमारी ने 3, पुनिता कुमारी ने 2, पूजा कुमारी और संजना उरांव ने 1-1 गोल कर झारखंड को पहले मुकाबले में जीत दिलाई। टीम में अनीशा उरांव, प्रतिभा भोक्ता, क्राति उरांव, नैना कुमारी, चांदनी कुमारी, उर्वशी कुमारी, संगीता कुमारी, बबिता कुमारी, संजना उरांव, पुनिता कुमारी, पूजा कुमारी, सोनामती होरो, एब्लिन कुजूर, पूनम कुमारी, ललिता बोयपाई शामिल हैं।

यूपीएससी आरटी परीक्षा की तैयारी को लेकर आयुक्त ने की मीटिंग

10 और 11 अगस्त को होगा एग्जाम

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची के कार्यालय कक्ष में आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरटी - तीन, चार, पांच, और छह की परीक्षा की तैयारियों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 10 और 11 अगस्त को होने वाले यूपीएससी आरटीएस परीक्षाओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में आयुक्त के सचिव जुल्फिकार अली, पुलिस पदाधिकारी, विभिन्न प्रखण्ड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। परीक्षा 10 और 11 अगस्त को दो पालियों में होगी। प्रथम पाली में पेपर -एक के लिए 9:30 बजे पूर्वाह्न से 11:30 बजे मध्याह्न तक और द्वितीय पाली में पेपर -दो के लिए 2 बजे अपराह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित है। परीक्षा के लिए राजकीय बालिका जमा दो उच्च विद्यालय, बरियातू, रांची को उप केंद्र बनाया गया है।

परीक्षा के बाद जीपीओ में जमा करने हैं कागजात

आयुक्त ने कहा कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी समय से प्रश्न पत्रों के पैकेट पहुंचाने एवं समाप्ति के पश्चात उत्तर पुस्तिका एवं अन्य आवश्यक कागजातों को जीपीओ में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाए तथा प्रतिनियुक्त पुलिस दल परीक्षा की तिथि को प्रातः 7:30 बजे तक कंसर्न ऑफिसर को रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करें। सभी परीक्षा उप केंद्रों पर विधि व्यवस्था संधारणार्थ एवं स्टैटिक दंडाधिकारी के साथ एक चार का पुलिस बल एवं एक अलग पुलिस दल जिसमें तीन पुरुष एवं दो महिला अनिवार्य रूप से प्रतिनियुक्त रहेंगे, जो परीक्षार्थियों के केंद्र में अंदर जाने के समय मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग सुनिश्चित करेंगे।

हर हाल में गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो : संतोष गंगवार

PHOTON NEWS RANCHI : राज्यपाल-सह-झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति डॉ. अजीत कुमार सिन्हा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति डॉ. सुनील चंद्र दुबे, झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति डॉ. डीके सिंह, झारखण्ड ओपेन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. टीएन साहु ने राजभवन में भेंट की एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत कराया। मौके पर राज्यपाल म ने उपस्थित सभी कुलपतियों से कहा कि विद्यार्थियों को हर हाल में गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो, हमारे विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें तथा एकेडमिक कैलेंडर का पूर्णतः पालन हो। हमारे विश्वविद्यालय छात्रहित में सदा सक्रियता से कार्य करें।

तमाड़ में दवा दुकान सहित आधा दर्जन दुकानें खाक

RANCHI : जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में ग्रामीण बाजार में आग लगने से छह दुकानें जल कर स्वाहा हो गईं। अगलगी की वारदात सोमवार देर रात की है। मौके पर पहुंचे फायर बिग्रेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची से जमशेदपुर की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे-33 स्थित भुईंयाडीह स्थित एक दवाई दुकान में सोमवार की देर रात आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आस पास के दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की घटना में अंकित मेडिकल स्टोर, गोपी किराना दुकान, विजय बीज भंडार, विष्णु साहू का जेनरल स्टोर, सुरेश गुप्ता का किराना दुकान जलकर राख हो गया है। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटे रांची-टाटा एनएच तक दिखाई दे रही थी।

न्यूजीलैंड के ऑक्लैंड सिटी हॉस्पिटल में जॉब लगाने की बात कहकर लगाया चूना

नौकरी दिलाने के नाम पर ₹1.66 करोड़ की ठगी

CRIME REPORTER RANCHI : न्यूजीलैंड में नौकरी के नाम पर 1.66 करोड़ रूपया ठगी कर ली गई। इस मामले की जांच को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता से शिकायत की गई है। यह शिकायत चाइल्ड राइट्स फॉउंडेशन के सचिव बैजनाथ कुमार के द्वारा मंगलवार को की गई है। शिकायत में कहा गया है कि गुमला जिला के बसिया का रहने वाला आवेदक विनेश कुमार साहु के माध्यम से पता चला कि डॉ. मीना एस गोप इनको बताया कि न्यूजीलैंड ऑक्लैंड सिटी हॉस्पिटल में नौकरी लगा देंगी। मीना एस गोप के माता-पिता इनके ही गांव सोनमेर के रहने वाले हैं। जिसे ये बहुत दिनों से जानती है। जो अभी गोवा में रहते हैं। ये उनके माता को फोन के माध्यम से पता किया तो उनके माता ने बताया कि बेटी मीणा छह वर्षों से न्यूजीलैंड में रहती है। तब इनलोगों को विश्वास हो गया। इसके बाद मीना एस गोप इनलोगों को अपने विश्वास में लेकर कहने लगी कि मैं न्यूजीलैंड ऑक्लैंड सिटी हॉस्पिटल की सेक्रेट्री हूं। इसके बाद इनलोगों को बहुत सारे प्रलोभन दी कि वीजा बनवा देगी और वहीं खाने रहने की सारी व्यवस्था करा देगी और महीने का एक लाख रुपया सैलेरी दिया जाएगा।

14 लोग हुए इस 'मायाजाल' का शिकार, डीजीपी से शिकायत

डीजीपी से किए गए शिकायत में कहा गया है कि मीना एस गोप ने कहा की न्यूजीलैंड ऑक्लैंड सिटी हॉस्पिटल में नीचे पद के लिए प्रति व्यक्ति चार लाख और उच्च पद के लिए आठ लाख और 12 लाख रूपया देना होगा तो इनलोगों ने कुल 14 लोगों का अलग-अलग तारीख को कुल 1.66 करोड़ रूपया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के पास विजय शर्मा नाम के व्यक्ति को दिया गया। जिसके बारे में इनलोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल करके पैसा लिफाफा में मीना एस गोप ने इनको देने के लिए कहती थी। काफी दिन बीत गये पर न इनलोगों को वीजा दिला पायी ना ही नौकरी दिलवायी। इनलोगों से नौकरी दिलाने के नाम से ठगी किया गया है। जब ये लोग

रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्पेशल क्विक रिस्पांस टीम तैनात

नियम तोड़ा तो विंड स्क्रीन पर नजर आएगा चालान

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए स्पेशल क्विक रिस्पांस (एसक्यूआरटी) टीम तैनात की गई है। बाइक सवार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दिनभर भ्रमणशील रहते हुए रांची की ट्रैफिक दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी दी गई है। राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस लगातार आलोचनाएं झेल रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट तक ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई बार पुलिस को फटकार लगा चुका है और कई तरह के आदेश भी दी गए हैं। ऐसे में रांची पुलिस के वरीय अधिकारी भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। ऐसे में रांची डीआईजी अनूप बीरथरे और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की पहल पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने लिए अब स्पेशल क्विक रिस्पांस टीम को ऑन किया गया है। मंगलवार को रांची डीआईजी और एसएसपी ने स्पेशल क्विक रिस्पांस टीम को हरी झंडी दिखाकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए रवाना किया। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची में जाम लगने की प्रमुख वजह बेतरतीब पार्किंग है। बेवजह जहां-तहां पार्क करने वालों में न सिर्फ कार चालक हैं, बल्कि बाइक सवार भी इसकी बड़ी वजह हैं। ऐसे में क्विक रिस्पांस टीम पूरे शहर में घूम-घूम कर बेवजह जहां-तहां अपने वाहन पार्क करने वाले लोगों पर कार्रवाई करेगी। स्पेशल टीम अवैध पार्किंग में पहुंच वाहनों के विंड स्क्रीन पर प्पहले नोटिस चिपकाएगी, जिसमें लिखा रहेगा कि आपकी गाड़ी गलत स्थान पर है। अगर इसके बावजूद वाहन चालक अपनी गलती नहीं सुधारेगा तो उसका फाइन काटा जाएगा। बता दें कि विंड स्क्रीन कार के वाइपर के नीचे का हिस्सा है। जहां वाइपर के साथ चालान को चिपका दिया जाएगा ताकि चालान यथास्थिति चिपका रहे।

10 बाइक की एक विशेष टीम का गठन

रांची डीआईजी अनूप बीरथरे ने बताया की डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर 10 बाइक की एक स्पेशल टीम बनाई गई है।डीजीपी के आदेश पर रांची एसएसपी ने टीम गठित की है, जिसे स्पेशल क्विक रिस्पांस टीम का नाम दिया गया है। इसके लिए 20 पुलिस कर्मियों को चयनित किया गया है। चयनित पुलिस कर्मियों को वायरलेस और सायरन युक्त 10 बाइक दी गई है। एक बाइक पर दो पुलिसकर्मी बैठ कर ट्रैफिक को नियंत्रण करने का काम करेंगे। डीआईजी के अनुसार शहर में अगर कहीं भी बहुत ज्यादा जाम की स्थिति होगी, वहां तुरंत स्पेशल टीम कूच करेगी और जाम को हटाने का काम करेगी।

476 पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए ₹1.72 करोड़ स्वीकृत

RANCHI : राज्य में तैनात 476 पुलिसकर्मियों के मेडिकल बिल को मंजूरी देते हुए 1.72 करोड़ की पुलिस मुख्यालय ने स्वीकृति दे दी। झारखंड पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष की बैठक में मंजूरी दी गयी। कल्याण कोष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जवानों के इलाज से संबंधित प्रस्तावित राशि को अंतिम स्वकृति मंजूर किया गया। शारीरिक रूप से बीमार पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को झारखंड पुलिस सहायता कल्याण कोष से बड़ी सहायता राशि मिलने की उम्मीद है। किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर जैसे गंभीर बीमारी के लिये झारखंड पुलिस सहाय एवं कल्याण कोष से उन पुलिसकर्मियों के लिए राहत राशि मंजूर की गई है, जिन्होंने इलाज के वास्ते पुलिस मुख्यालय में आवेदन दिया था। यह राशि पांच हजार रुपये से लेकर 1.20 लाख तक निर्धारित की गई है। 516 पुलिसकर्मियों ने आवेदन दिया था, जिसमें 40 पर स्वीकृति नहीं दी गई।

बाबूलाल का हेमंत सरकार पर वार, कहा-

चोरों का आतंक अंधेरे की गहराई से अधिक भयावह

PHOTON NEWS RANCHI : बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के लिए राजकीय एंथम लिखा है। उन्होंने ट्वीट कर एंथम में लिखा है कि जीना है तो डर के जियो, जीवन में एक पल भी हंसना न, कहा है कि प्रदेश में आए दिन हो रही चोरी से एक बार तो स्पष्ट हो चुकी है कि चोरों को सरंक्षण देने वाली हेमंत सरकार ने झारखंड में चोरी को राजकीय व्यवसाय मान लिया है, तभी तो चोरी और चोरों पर कार्यवाही करने के बजाव उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। झारखंड में चोरों का आतंक अंधेरे की गहराई से अधिक भयावह हो चुका है, अब झारखंड का हाल ऐसा हो गया है कि लोगों को अंधेरों से ज्यादा, चोरों से डर लगने लगा है। अंधेरे की शिकायत तो फिर भी सूरज से की जा सकती है, लेकिन चोरी की शिकायत किससे की जाए! शासन- प्रशासन तो चोरों को तथा उनकी चोरी को बचाने में लगा हुआ है। दूसरे ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि झारखंड में जैसे मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों का मन डोलता रहता है, ठीक वैसे ही सरकारी भवनों की नींव भी डोल रही है, कब, कैसे, किसके ऊपर ये गिर जाएं, ज्योतिषी भी नहीं बता सकते हैं।

डिमना डैम में डॉक्टरों को लूटने वाले नाबालिग समेत सात हुए गिरफ्तार

मानगो के रंगदारी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मिला लूट का सुराग

PHOTON NEWS JSR: जमशेदपुर पुलिस ने बोड़ाम थाना अंतर्गत डिमना डैम के पास विगत 26 जून को अवध डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों से लूट और मानगो में रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा किया है। डॉक्टरों से लूट के मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत सभी सात एवं रंगदारी मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तार दो आरोपी इन दोनों ही मामलों में वांछित थे। लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपियों में मानगो कुंवर बस्ती निवासी विशाल सिंह, मानगो गुरुद्वारा बस्ती निवासी मोहित बर्मन, मून सिटी निवासी शंकर महतो उर्फ सूरज महतो, राजा सिंह, देवा राव और टुनटुन यादव शामिल है। वहीं रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार आरोपी उलीडीह निवासी योगेंद्र जोशी उर्फ मोनू बताया जाता है। मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी सह प्रभारी सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि 26 जून को अवध डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉ. सौभिक आश अपने तीन साथियों के साथ रात 11 बजे डिमना डैम की ओर गए थे।

उसी दौरान विशाल सिंह, मोहित, शंकर, राजा, देवा, टुनटुन, और एक नाबालिग ने उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की। उनके पास पैसे नहीं थे, तो आरोपियों ने डॉ. सौभिक से ऑनलाइन 24,600 रुपये ट्रांसफर कराए और फरार हो गए। इसी बीच योगेंद्र जोशी ने विशाल और मोहित के साथ मिलकर मानगो चौक पर गैरेज चलाने वाले व्यक्ति से रंगदारी मांगी थी।

जानकारी देते एसपी ऋषभ गर्ग व अन्य पदाधिकारी ● फोटोन न्यूज

योगेंद्र जोशी के गिरफ्तार होने पर हुआ खुलासा

एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि मानगो पुलिस ने पहले रंगदारी मांगने के आरोप में योगेंद्र जोशी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद विशाल और मोहित की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में विशाल और मोहित ने बताया कि उन्होंने अन्य साथियों के साथ मिलकर डिमना डैम के पास लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद मानगो पुलिस ने बोड़ाम पुलिस से संपर्क साधा और लूट के मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की। पुलिस ने फिलहाल नाबालिग को बाल सुधार गृह तथा अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया है।

आदित्यपुर के होटल के कमरे में अमलगम कंपनी के अधिकारी का शव बरामद

SARAIKELA : जमशेदपुर से सटे सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा-कांड्रा मुख्य मार्ग स्थित होटल क्रूज के कमरा नंबर 315 से एक व्यक्ति का शव पाया गया। मृतक की पहचान कांड्रा स्थित अमलगम कंपनी के अधिकारी एस रंजन दास के रूप में की गई। रंजन 4 अगस्त से होटल में ठहरे हुए थे। सूचना पाकर आदित्यपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर टीएमएच के शवगृह में रखवा दिया। पुलिस परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के आवेदन के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक मूल रूप से ओडिशा स्थित खुर्दा के रहने वाले हैं।

गोशाला परिसर की छत गिरी, तीन मवेशियों की मौत

JAMSHEDPUR : जुगसलाई थाना अंतर्गत गोशाला परिसर की दीवार मंगलवार सुबह अचानक गिर गई, जिसके नीचे दबकर तीन मवेशियों की मौत हो गई। इसके अलावा कई मवेशियों के मलबे के नीचे दबे होने की सूचना है। घटना मंगलवार तड़के 4 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद गोशाला प्रबंधन के बीच हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि गोशाला के बगल निर्माणाधीन मार्केट कांप्लेक्स के लिए खोदे गड्ढे की वजह से यह घटना घटी है। इसमें तीन गायों की मलबे में दबने से मौत हो गई और कुछ गाय घायल हो गईं। मलबे के हटाने पर मृत मवेशियों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल मलबे को हटाने का काम जारी है। इधर, मामले की शिकायत पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पशु प्रेमी मेनका गांधी से की गई। मेनका गांधी ने मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जुगसलाई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी से बात कर गोशाला के बगल में चल रहे निर्माण कार्य को बंद करने का निवेदन किया और दोषियों पर कार्रवाई करने को भी कहा।

खदेड़कर पुलिस ने हथियार के साथ दो अपराधियों को दबोचा

अपराधियों की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : एमजीएम थाना की पुलिस ने एनएच-33 पर ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पदार्फाश किया है। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग गए। गिरफ्तार आरोपियों में गोलमुरी टुइलाडुंगरी निवासी जसपाल सिंह और काशीडीह लाइन नंबर 1 निवासी राजदीप सिंह शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक लोडेड देसी पिस्टल, एक चाकू, तीन मोबाइल और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। दरअसल, बीते कई दिनों से एनएच पर ट्रक चालकों से लूट की घटना सामने आ रही थी। अपराधी ट्रक को रोककर चालकों से 1ञ2 हजार रुपये ही लूटते थे। लूट की रकम कम होने की वजह से चालक थाने में शिकायत भी नहीं करते थे। हालांकि, पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस एनएच पर एक्टिव हो गई। मंगलवार तड़के पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ युवक एक कार में लूट के उद्देश्य से घूम रहे हैं। पुलिस ने मुखियाडांगा के पास चेकनाका बनाया। इसी बीच घाटशिला की ओर से आ रही एक कार पुलिस को देखकर जमशेदपुर की ओर भागने लगी। पुलिस ने दो किमी तक कार का पीछा किया और बालीगुमा के पास कार को ओवरटेक कर पकड़ा। इस दौरान तीन युवक फरार हो गए।

जुगसलाई फाटक पर एफओबी निर्माण को ले 25 झोपड़ी ध्वस्त

झोपड़ी को तोड़ता बुलडोजर ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : जुगसलाई रेलवे फाटक के पास मंगलवार को रेलवे लैंड डिपार्मेंट द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें फाटक के आसपास की 25 झुग्गी-झोपड़ी को ध्वस्त किया गया। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में आरपीएफ के जवान और स्थानीय थाने की पुलिस मौजूद थी। इससे पूर्व लैंड डिपार्मेंट द्वारा जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग के दोनों छोर पर रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को नोटिस दिया गया था, ताकि वे जल्द से जल्द स्थान खाली कर दें। समयसीमा समाप्त होने के बाद रेलवे क्रॉसिंग के दोनों छोर पर रेलवे की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। लैंड डिपार्मेंट के एसएसई संजय गुप्ता ने बताया कि जिस तरह से रेलवे ट्रैक के किनारे अतिक्रमण किया गया है, वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी घातक है।

दपू रेलवे के नए वरिष्ठ उप महाप्रबंधक सुरिंदर पाल ने संभाला पदभार

JAMSHEDPUR : दक्षिण पूर्व रेलवे के नए वरिष्ठ उप महाप्रबंधक सुरिंदर पाल ने मंगलवार को जोनल मुख्यालय गार्डनरीच, कोलकाता में पदभार संभाल लिया। इससे पहले वे चंडीगढ़ में रेल भूमि विकास प्राधिकरण के मुख्य परियोजना प्रबंधक थे। 1990 बैच के आईआरईएस अधिकारी सुरिंदर पाल मार्च 1992 में भारतीय रेलवे में शामिल हुए और परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद वर्ष 1994 में जम्मू-उधमपुर रेल लिंक की प्रतिष्ठित परियोजना पर तैनात हुए। सुरिंदर पाल ने एनआईटी, कुरूक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की है।

नीतीश बने भाजयुमो जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष, रंगलाल महतो ग्रामीण जिलाध्यक्ष

अनुराग को सरायकेला-खरसावां व चंद्रमोहन को पश्चिमी सिंहभूम की कमान

PHOTON NEWS JSR: बागबेड़ा निवासी नीतीश कुशवाहा भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं। छात्र जीवन से राजनीति की शुरूआत करनेवाले नीतीश वर्ष 2016 में जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज छात्र संघ एवं कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने के साथ ही भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के लिए मोर्चा के महानगर एवं जिलाध्यक्षों की सूची जारी करते हुए नीतीश को जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष बनाये जाने की सूचना व बधाई दी।

इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया है कि नीतीश के नेतृत्व में जिले में मोर्चा और भी मजबूत एवं सशक्त होगा। सूची में 27 महानगर व जिलाध्यक्षों के नाम शामिल हैं। सूची के अनुसार रंगलाल महतो को मोर्चा का पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुराग जायसवाल को सरायकेला-खरसावां तथा चंद्रमोहन तियु को पश्चिमी सिंहभूम का जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

नीतीश कुशवाहा

दोबारा प्रदेश उपाध्यक्ष बने विमल बैठा

JAMSHEDPUR : विमल बैठा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर के दोबारा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसे लेकर साकची स्थित जिला कार्यालय में बैठा का स्वागत किया गया। मोर्चा के जिला महामंत्री पीके करुवा के नेतृत्व में सभी जिला पदाधिकारियों ने विमल बैठा को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया।

समाचार सार

जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी में बजट पर हुई चर्चा

JAMSHEDPUR : सिदगोड़ा स्थित जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी में मंगलवार को कॉमर्स विभाग ने अंतरराष्ट्रीय कॉमर्स दिवस मनाया। कुलपति डॉ. अंजिला गुप्ता ने कार्यक्रम की शुरूआत की, जिसके बाद मुख्य वक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट शिव चौधरी तथा कंपनी सेक्रेटरी सुरोजित भूमिज ने केंद्रीय बजट-2024 पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस बार के आम बजट में पूंजी लाभ में मूल्य सूचकांक को हटाया तथा स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार किया गया है। इससे पूर्व यूनिवर्सिटी की कॉमर्स विभागाध्यक्ष सह डीन डॉ. दीपा शरण ने स्वागत भाषण देते हुए अंतरराष्ट्रीय कॉमर्स दिवस की महत्ता बतायी। कार्यक्रम में डॉ. कामिनी कुमारी, डॉ. ग्लोरिया पूर्ति तथा डॉ. छगनलाल अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। मंच संचालन भावना कुमारी व श्वेता पटेल ने किया।

इनर व्हील ने चलाया स्तनपान जागरूकता अभियान

JAMSHEDPUR : इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट ने मंगलवार को विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर निभा मिश्रा ने स्तनपान की विशेषताओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में आईएसओ निवेदिता सिन्हा, सचिव अंतरा चक्रवर्ती, उपाध्यक्ष सनोवर हुसैन, संपादिका उषा महतो और सदस्य अनिंदिता बेरा, रजनी गन्टा, बर्नाली लाहिड़ी, अनुसोहन पाल तथा जया चौधरी का योगदान रहा।

रोटरी फेमिना ने चेशायर होम में पहुंचाई मदद

JAMSHEDPUR : रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर फेमिना की ओर से अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट (फूड फॉर हैप्पीनेस) के तहत सुंदरनगर स्थित चेशायर होम में 105 किलो चावल और 30 किलो दाल दान किया गया। वर्तमान समय में चेशायर होम में कुल 80 सदस्य रहते हैं। इस मौके पर अध्यक्ष सीमा कुमार, पास्ट प्रेसिडेंट मोनीदीपा दंडपात सहित व अन्य रोटेरियन उपस्थित थे।

नाई समाज के सामुदायिक भवन का भूमिपूजन

JAMSHEDPUR : गोविंदपुर में नाई समाज के सामुदायिक भवन का भूमिपूजन मंगलवार को हुआ। इस मौके पर जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी एवं जिला परिषद सदस्य डॉ. परितोष सिंह उपस्थित थे। इस अवसर विधायक ने कहा कि नाई समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं था। इसे देखते हुए गोविंदपुर में खाता संख्या 265 प्लॉट संख्या 694 में अंचलाधिकारी के द्वारा 10 डिसमिल जमीन आवंटित किया गया था। इस अवसर पर नाई समाज के स्थानीय अध्यक्ष राजू ठाकुर, सचिव उमेश ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, पापुन प्रमाणिक, गोविंद ठाकुर, आदित्य ठाकुर आदि उपस्थित थे।

बांग्लादेश में शांति सेना भेजे यूएनओ : भाजपा

JAMSHEDPUR : भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं, वहां देवी-देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ को बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्काल शांति सेना भेजनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर हालात वहां की पुलिस और सेना नहीं संभाल पा रही है तो इस स्थिति में बांग्लादेश 1971 की तरह भारत सरकार से मदद ले। इसके साथ ही सुधांशु ओझा ने झारखंड सरकार से अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम लगाने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को जटिल समस्या मानकर उनकी बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए झारखंड सरकार से ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। उधर, शहर के हिंदू नेता **चिंटू सिंह** ने बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध लक्षित हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार एवं सैन्य बलों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिंदुओं के विरुद्ध लक्षित हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो भारत में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और विशेषकर हिंदू महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बेहद चिंताजनक है।

डॉ. अजय ने भुइयांडीह के लोगों से की मुलाकात, बंधाया ढाढस

एनजीटी में 23 को अधिवक्ता संदीप बनर्जी रखेंगे भुइयांडीह के लोगों का पक्ष

PHOTON NEWS JSR: भुइयांडीह के कल्याण नगर, राधिका नगर और छायानगर सहित स्वर्णरेखा नदी तट पर बसे 150 परिवार के लोगों से मंगलवार को पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉ. अजय कुमार ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अब केवल आपकी लड़ाई नहीं रह गई। हम इसको अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार के रहते एक भी घर टूटने नहीं दिया जाएगा। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गंभीर हैं। उन्होंने इस संबंध में वरीय आधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डॉ. अजय ने लोगों को बताया कि 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता संदीप बनर्जी एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) में भुइयांडीह के लोगों का पक्ष रखेंगे। इसका पूरा खर्च वो स्वयं वहन करेंगे। उन्होंने बताया कि एनजीटी द्वारा दी गई नोटिस के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायलय में याचिका दायर की जा चुकी है। अटॉर्नी जनरल राजीव रंजन ने आश्वस्त किया है कि लोगों के घरों के बचाने को लेकर सरकार एनजीटी में अपना पक्ष रखेगी। डॉ. अजय ने कहा कि आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरुरत नहीं है।

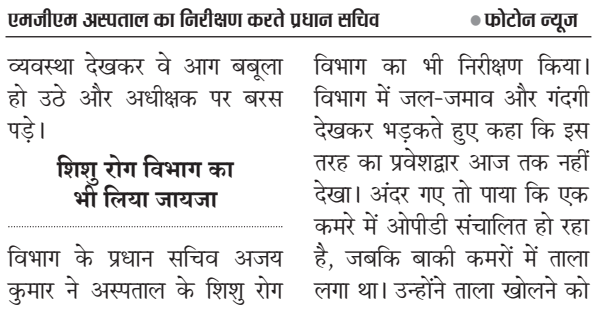

बस्तीवासियों से बात करते डॉ. अजय कुमार ● फोटोन न्यूज

जेटीईटी परीक्षा में छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़ : एडसो

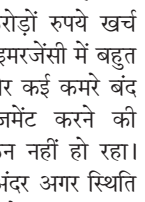

GHATSILA : झारखंड शिक्षण योग्यता परीक्षा (जेटीईटी) होने जा रहा है। सरकार के इस फैसले से शिक्षण प्रशिक्षकों में काफी उत्साह है, परंतु दूसरी ओर झारखंड के हजारों छात्रों के बीच हताशा और उदासीनता का माहौल है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स आगेर्नाइजेशन (एआईडीएसओ या एडसो) के राज्य सचिव सोहन महतो ने कहा कि सरकार व संबंधित संस्थाओं ने परीक्षा आयोजन करने का संभावित तिथि सितंबर के दूसरे सप्ताह में घोषित कर दी है, परंतु जेटीईटी की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा, इसे अभी तक जारी किया नहीं गया है, जबकि परीक्षा के लिए महीने भर से भी कम समय बचा है।

जुगसलाई में हड़ताल पर गए सफाई कर्मी

नगर परिषद कार्यालय के पास जुटे सफाई कर्मचारी ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : क्यूब वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा उठाव कराया जाता है। मंगलवार को समय पर वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने अपना काम बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। श्रम कानून को पालन करने, अपर श्रमायुक्त के साथ हुई त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने, झारखंड सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने, समय पर वेतन देने, ईएसआईसी और पीएफ घोटाला बंद करने समेत विभिन्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग करते हुए ड़ोर टू डोर कचरा उठाने वाले सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इनके द्वारा जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए काम बंद कर दिया गया है। इनका साथ अन्य सफाई कर्मियों ने भी दिया और अपने-अपने काम को बाधित कर दिया।

एमजीएम अस्पताल में फर्श पर बैठ कर स्तनपान करा रही थीं महिलाएं, कई कमरे बंद पाए गए, जंग लगी मशीनें भी दिखीं

लचर व्यवस्था पर बिफरे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, अधीक्षक पर बरसे

PHOTON NEWS JSR : स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, रेडियोलॉजी और आयुष्मान विभाग के अलावा अन्य विभागों का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल के अधीक्षक डॉ. रविंद्र कुमार, उपाधीक्षक नकुल चौधरी समेत अस्पताल के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान अजय कुमार पहले इमरजेंसी विभाग गए, जहां मरीजों की भीड़ और लचर व्यवथा देखकर नाराजगी जतायी। इमरजेंसी वार्ड में उन्होंने बंद कमरों को भी खोलकर देखा, जहां कई महंगी मशीन पड़ी थी और उनमें जंग लगा था। आईसीयू वार्ड की व्यवस्था देखकर वे आग बबूला हो उठे और अधीक्षक पर बरस पड़े।

एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण करते प्रधान सचिव ● फोटोन न्यूज

शिशु रोग विभाग का भी लिया जायजा

विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार ने अस्पताल के शिशु रोग विभाग का भी निरीक्षण किया। विभाग में जल-जमाव और गंदगी देखकर भड़कते हुए कहा कि इस तरह का प्रवेशद्वार आज तक नहीं देखा। अंदर गए तो पाया कि एक कमरे में ओपीडी संचालित हो रहा है, जबकि बाकी कमरों में ताला लगा था। उन्होंने ताला खोलने को कहा। इन सभी कमरों में भी कई महंगी मशीन जंग लगी थी। उन्होंने बंद कमरे को खोलकर उसका उपयोग करने का निर्देश दिया।

इमरजेंसी के मरीजों को यहां शिफ्ट करने को भी प्रधान सचिव ने कहा। इसके बाद वे एनआइसीयू-पीआइसीयू पहुंचे। वहां महिलाएं फर्श पर बैठकर स्तनपान करा रही थीं। अजय कुमार ने कहा कि अस्पताल पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इमरजेंसी में बहुत सारे मरीज हैं और कई कमरे बंद हैं। इसका मैनेजमेंट करने की जरूरत है, लेकिन नहीं हो रहा। एक सप्ताह के अंदर अगर स्थिति में सुधार नहीं हुई तो विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षक व उपाधीक्षक के साथ ही विभागाध्यक्ष भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुसा पानी

इमरजेंसी वार्ड से पानी निकालता सफाई कर्मी ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : शहर में मंगलवार को हुई भारी बारिश के कारण एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी घुस गया। इमरजेंसी वार्ड के नए हिस्से (न्यू इमरजेंसी), जिसे विस्तारित कर बनाया गया था, में पानी घुसने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी होने लगी। यहां मौजूद नर्सों ने सफाई कर्मचारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही एमजीएम अस्पताल के सफाई कर्मियों ने पानी निकालने और सफाई का काम शुरू कर दिया। इसके बाद पानी निकला।

भारत में बायोटेक इंडस्ट्री का कारोबार हर साल करीब 11 अरब डॉलर का है। सरकार ने 2025 तक इसकी कैपेसिटी को 100 अरब डॉलर पहुंचाना तय किया है। इस वजह से इस सेक्टर में आगामी सालों में नौकरियों के सबसे ज्यादा मौके नजर आ रहे हैं।

बायोटेक इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं

हमारे देश में बायोटेक इंडस्ट्री हर साल 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। भारत में हर साल इसका कारोबार करीब 11 अरब डॉलर का है। सरकार ने 2025 तक इसकी कैपेसिटी को 100 अरब डॉलर पहुंचाना तय किया है। इस वजह से इस सेक्टर में आगामी सालों में नौकरियों के सबसे ज्यादा मौके नजर आ रहे हैं। नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अनुसार अगले पांच साल में इस सेक्टर में 7 से 8 लाख नई नौकरियां मिलने का अनुमान है। यानी हर साल एक लाख से भी ज्यादा नौकरियां यहां मिल सकती हैं।

जरूरत से कम प्रोफेशनल्स यानी मौके ही मौके

इस सेक्टर में कितना स्कोप है, इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि देश के 300 से ज्यादा संस्थानों से करीब 50 हजार बायोटेक प्रोफेशनल हर साल निकलते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में हर साल करीब 80 हजार प्रोफेशनल्स की जरूरत है। बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री ले चुके छात्रों के लिए नौकरी के अवसर ड्रग एंड फार्मास्युटिकल, केमिकल, एनवायरनमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग और बायो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हैं। इसके इलावा अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों में रिसर्च साइंटिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, एनालिस्ट, सेफ्टी स्पेशलिस्ट जैसे पदों पर उनके लिए अवसर हो सकते हैं। इसके अलावा देशभर में 100 से ज्यादा रिसर्च लैबोरेटरी हैं, जिनमें हर साल हजारों लोगों को नियुक्त किया जाता है।

कहां से कर सकते हैं कोर्स?

बायोटेक्नोलॉजी के यूजी और मास्टर कोर्स देशभर के संस्थानों में मौजूद हैं। साइंस स्ट्रीम में 10+2 कर चुके छात्र अंडरग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का बीटेक कोर्स कुछ आईआईटी संस्थानों में भी उपलब्ध है। इसमें प्रवेश जेईई एडवांस के आधार पर मिलता है और हर सीट के लिए 100 से ज्यादा आवेदक होते हैं। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में बैचलर डिग्री ले चुके छात्र मास्टर कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। अधिकतर संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमिशन मिलता है।

सैलरी

यूजी कोर्स करने के बाद एंट्री लेने वाले छात्रों का शुरुआती पैकेज 3 से 4 लाख रुपए सालाना तक हो सकता है। एक दो साल के अनुभव के बाद यह रकम 6 लाख से ज्यादा हो सकती है। मास्टर या पीएचडी डिग्री ले चुके छात्रों के लिए नौकरी के अवसर ज्यादा होते हैं और उन्हें पैकेज भी ज्यादा मिलता है। रिसर्च संस्थानों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को शुरुआत में ही 5 लाख रुपए तक का पैकेज मिल सकता है।

देश में हैं 800 से ज्यादा कंपनियां

देश में बायोटेक्नोलॉजी की 800 से ज्यादा कंपनियां हैं। इसके अलावा देशी-विदेशी संस्थाओं में भी छात्रों के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं।कृषि, हेल्थकेयर व अन्य क्षेत्रों में बढ़ा उपयोग देश की 50 फीसदी से ज्यादा आबादी के जीवनयापन का जरिया कृषि है, लेकिन घटती पैदावार खाद्य सुरक्षा के लिए संकट है। बायोटेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल से हालात में सुधार हो सकते हैं। हेल्थकेयर, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, फूड इंडस्ट्री आदि में भी ये तकनीकें कारगर हो सकती हैं। बायोफार्मा सेक्टर अकेले ही देश की अर्थव्यवस्था में 2 अरब डॉलर से ज्यादा का योगदान दे सकता है।

अगर आप वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूलों में एडमिशन लेने का ख्वाब संजो रहे हैं इसके लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको बता रहे हैं इन स्कूलों में दाखिले के लिए जाने वाले ऐसे टेस्ट के बारे में जिनको पास करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं।

दुनिया के बेस्ट बी स्कूलों में दाखिले के लिए दें यह टेस्ट

हर किसी का सपना होता है कि वह जिस स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण करें वह दुनिया के टॉप स्कूलों में से हो। अगर आप वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूलों में एडमिशन लेने का ख्वाब संजो रहे हैं इसके लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको बता रहे हैं इन स्कूलों में दाखिले के लिए जाने वाले ऐसे टेस्ट के बारे में जिनको पास करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। पहला जीमैट यानि Graduate Management Admission Test - GMAT और दूसरा जीआरई Graduate Record Examination - GRE। बहुत से स्टूडेंटस जीमैट और जीआरई की अहमियत और मान्यता को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। दरअसल जीमैट एक इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है जिसे देकर आप दुनिया के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों के एमबीए, मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी और मास्टर ऑफ फाइनेंस जैसे मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं जीआरई एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसके जरिए सभी पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है। ज्यादातर छात्र, जो कि विदेश से एमबीए करना चाहते हैं, जीमैट परीक्षा ही देते हैं। जीमैट एमबीए के लिए एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है।

क्या है दोनों में फर्क

जीमैट और जीआरई दोनों ही एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट है। लेकिन इन दोनों परीक्षाओं की प्रकृति और सामग्री अलग-अलग होती है। जीमैट टेस्ट का स्कोर 5 साल के लिए मान्य रहता है। साल में किसी भी समय आप www.mba.com पर जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दुनिया भर में इसके 600 टेस्ट सेंटर हैं।

जीमैट का स्कोर 82 देशों के करीब 1600 संस्थान स्वीकार कर रहे हैं। भारत के 90 से ज्यादा बी-स्कूल जीमैट स्कोर के आधार पर एडमिशन देते हैं।

जीआरई का बढ़ता चलन

कुछ सर्वेक्षणों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जीआरई देने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। ब्रिटेन और अमेरिका में बड़ी तादाद में बी-स्कूल जीआरई में हासिल किए अंकों के आधार पर ही दाखिला दे रहे हैं। वैसे तो जीआरई कंप्यूटर और पेपर-बेस्ड दोनों फॉरमेट में करवाया जाता है लेकिन भारत में यह सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड फॉरमेट में ही होता है। दुनिया भर के 1200 से ज्यादा संस्थान इस टेस्ट के स्कोर को स्वीकार करते हैं। इसे भी साल में अधिकतम पांच बार दिया जा सकता है। दो प्रयासों में कम से कम 21 दिन का गैप जरूरी हो।

कौन दे सकता हैं ये टेस्ट

वैसे तो इन परीक्षाओं को ग्रजुएट उम्मीदवार बैठ सकते हैं लेकिन विभिन्न संस्थानों का चयन का तरीका एक-दूसरे से अलग हो सकता है। एक साल में 5 बार जीमैट दिया जा सकता है। लेकिन दो प्रयासों के बीच में 16 दिन का अंतराल होना जरूरी है।

इंटरव्यू के दौरान अपनाएं यह ट्रिक्स

आज के दौर में जॉब पाना मुश्किल होता जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपने इंटरव्यू के लिए कितनी मेहनत की होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमने इंटरव्यू में पूछे सारे सवालों का सही जवाब दिया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें जॉब के लिए बुलावा क्यों नहीं आया। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते है, लेकिन ज्यादातर यह होता है कि आपसे संतुष्ट नहीं होते, या आप सवालों के जवाब इतने प्रभावी तरीके से नहीं दे पाते।

इंटरव्यू का मकसद सिर्फ कर्मचारी के बारे में जानने या उससे मिलने के लिए नहीं लिया जाता, बल्कि कंपनी में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी इंटरव्यू के बहाने आपके बारे में भी बहुत कुछ जान लेते हैं। इसलिए किसी भी जगह इंटरव्यू देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इंटरव्यू में लेने वाले अधिकारियों पर अपना पॉजीटिव प्रभाव छोड़ सकें।

पहली कंपनी की बुराई ना करें

कई बार लोग इंटरव्यू के दौरान अपने पहले जॉब को कोसते है और संस्थान के बारे में जी भर कर बुराई करते है। इन बातों का इंटरव्यू लेने वालों पर निगेटिव असर होता है। असल में हर बड़ी कंपनी के नियम, स्ट्रक्चर और व्यवस्थाएं लगभग एक जैसी ही होती हैं। इसलिए ऐसी बातों से जॉब न मिलने की आशंका बढ़ जाती हैं। जिनके साथ काम करते हैं, उन्हें कम न समझें जब भी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो यह ध्यान रखें कि पहले के संस्थान में काम करने वाले किसी कैंडिडेट के बारे निगेटिव न बोलें। इंटरव्यू लेने वाले के सामने अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करें। कोई भी कंपनी हो वह ऐसे कैंडीडेट को ज्यादा तवज्जो देती है जो खुद से निकलकर टीम भावना को लेकर चलता है।

ध्यान न भटकने दें

इंटरव्यू के दौरान अपना ध्यान सिर्फ वहीं फोकस रखें। एक इंटरव्यू के दौरान दूसरे जॉब के बारे में न सोचें। इससे हो सकता है कि आपके आव-भाव में कहीं कोई कमी नजर आने लगे। इससे आप सवालों का सहज जवाब भी नहीं दे पाते। इंटरव्यू में गलती से भी किसी फोन कॉल को अटेंड न करें। इंटरव्यू के बाद आप भले ही कॉल बैक कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी कमरे से बाहर भी निकाल सकते हैं।

अतिरिक्त प्रयास करने से बचें

बहुत से लोग इंटरव्यू पैनल को खुद करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करते हैं। यह सही तरीका नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते है तो हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल को लगे कि आपमें अपने जवाब को लेकर आत्मविश्वास की कमी है, इस वजह से आप अपने जवाब पर बार-बार जो दे रहे हैं। ऐसे केंडिडेट के सेलेक्ट होने के चांस कम होते हैं।

फर्स्ट इंप्रेशन

इंटरव्यू के दौरान यह ध्यान रखें कि आपका पहला इंप्रेशन बहुत प्रभावी होता है। आपकी ड्रेस, आपकी एंट्री इंटरव्यू पैनल पर प्रभाव छोड़ते हैं। कोशिश करें कि पहले सवाल के जवाब देने के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेंज में आत्मविश्वास हो।

कंपनी के बारे में रखें जानकारी

इंटरव्यू से पहले ज्यादातर लोगों को कंपनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती ।आपके पास कितनी भी स्किल्स हो या आपकी क्वालिफिकेशन्स आपको योग्य उम्मीदवार साबित करती हो लेकिन कंपनी के बारे में जानकारी न होना आपके लिए रेड सिग्नल साबित हो सकता है।

विश्व युद्ध का अंदेशा और बांग्लादेश में सेना का तख्ता पलट

डॉ हिदायत अहमद खान

सेना प्रमुख जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि देश में इस समय कर्फ्यू या आपातकाल लगाने की आवश्यक्ता नहीं है। रातों-रात समस्या का समाधान निकालने की बात भी की जा रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं यह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पदच्युत करने की साजिश का हिस्सा तो नहीं था, जिसमें पूरी सरकार ही फंस गई। इतिहास दोहराने जैसा काम भी यह लगता है।

पिछले कुछ समय से दुनियां के शक्तिशाली देशों के हालात सही नहीं चल रहे हैं। विकसित ही क्यों विकासशील छोटे-छोटे देशों का हाल भी बुरा है। इसे आर्थिकमंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहे हैं और मंदी के चलते महंगाई चरम पर है। इस पर विकट समस्या यह है कि अधिकांश देश अपने पड़ोसी देश को दुश्मन देश मानकर हमले करने पर उतारु दिख रहे हैं। पड़ोसी देश एक-दूसरे से या तो लड़ रहे हैं या फिर लड़ने को आतुर नजर आ रहे हैं। बात कुछ भी न हो, तब भी तनातनी का माहौल बराबर बना हुआ है। यहां देखा जा सकता है कि एक तरफ रुस और यूक्रेन भिड़े हुए हैं। दूसरी तरफ हमास के हमले के बाद इजराइल अमेरिका की मेहरबानी से गाजा में फिलस्तीन से लेकर तमाम पडोसी मुल्कों से भिड़ने का दंभ भरे हुए है। हमास चीफ हानिया को ईरान में साजिशन हत्या कराए जाने के बाद मामला और बिगड़ चुका है। दुश्मनों से घिरे इजराइल को ढांढस बंधाने का काम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईडन कर तो रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी भी तो परेशानियां हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाने का काम किया वैसे ही रुस भी अमेरिका के खिलाफ उत्तर कोरिया को इस संकट वाली स्थिति में खड़ा कर सकता है। ऐसा इसलिए भी कहना उचित होगा, क्योंकि उत्तर कोरिया के प्रमुख नेता किम जोंग उन ने अपनी फ्रंट लाइन आर्मी यूनिट को 250 परमाणु सक्षम मिसाइल लांचर तैनात करने के लिए उपलब्ध करा दिए हैं। यही नहीं किम जोंग उन ने तो अमेरिकी खतरे का मुकाबला करने के लिए सेना को परमाणु क्षमताओं को और बढ़ाने का संदेश देते हुए तैयार रहने को भी कह ही दिया। इस प्रकार उत्तर कोरिया का परमाणु हथियारों पर जोर देने का मकसद दक्षिण कोरियाई सीमा पर सेना को मजबूत करना तो बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अमेरिका को आंख दिखाने जैसा यह काम किया गया है। इनकी तैनाती बताती है कि दक्षिण कोरिया के साथ ही अमेरिका की राहें भी अब मुश्किल होने वाली हैं। यदि इजराइल की नेतन्याहू सरकार के बचाव में अमेरिका कदम आगे बढ़ाता है तो एक महायुद्ध का बिगुल भी बज जाएगा। इससे महज गाजा और आसपास के देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी संकट के बादल छा जाएंगे। अनेक देश तब युद्धभूमि का हिस्सा होने के तौर पर चिहिन्त किए जाएंगे। ऐसे में अमेरिका को उसके अपने घर में चुनौती देने वाली ताकतें भी फिर चुप न बैठेंगी। बहरहाल यहां हम बात बांग्लादेश के सैन्य तख्ता पलट कर करने जा रहे हैं, जहां छात्र आंदोलन ने हिंसक रुप लेकर सब कुछ तहस-नहस करने जैसा कर दिखाया है।

ऐसे माहौल में जब हम अपनी नजरें भारत और उसके तमाम पड़ोसी मुल्कों के हालात पर डालते हैं तो पाते हैं कि यहां पर भी कोई बेहतर स्थिति नहीं है। सभी अपनी घरेलु समस्याओं में उलझे हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक हालात भी बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। पाकिस्तान में तो मौजूदा सरकार की स्थिरता को लेकर ही शंकाएं विद्यमान हैं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी को लेकर पाकिस्तान की राजनीति आज तक गर्माई हुई है। ऐसे में बलूच मामले ने भी तूल पकड़ा हुआ है। बलूच समर्थक लोग तो पुलिस व सेना से दो-दो हाथ करने को आतुर दिखते हैं। यह मामला अभी चल ही रहा था कि बांग्लादेश से सेना का तख्ता पलट की अचानक अचंभित करने वाली खबर भी आ गई है। बांग्लादेश में आरक्षण की आग जंगल में लगी आग साबित हुई है। इस मामले को लेकर हिंसक प्रदर्शन, मौतों के बढ़ते आंकड़े और इसी बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का अपने पद से इस्तीफा दे देना। पूर्व नियोजित तो कदापी नहीं था, लेकिन देश के हालात इस कदर बिगड़े कि शेख हसीना को देश ही छोड़ देना पड़ा है। अब सेना ने देश की कमान संभाल ली है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं कि बहुत जल्द बांग्लादेश के हालात सुधरने जा रहे हैं। इस पूरे मामले में जमात-ए-इस्लामी को बैन करना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तौर पर एक शक्तिशाली संगठन होने के नाते देश की राजनीतक शतरंज में जमात-ए-इस्लामी के लीडरों का रोल अहम माना जा रहा है। ऐसे में शेख हसीना का बतौर प्रधानमंत्री वाला अध्याय भले ही क्लोज हो गया हो, लेकिन देश में सेना के इशारे पर अंतरिम सरकार कौन चलाएगा और किन मुद्दों पर किस तरह से फैसला लिया जाएगा, अभी इस पर बराबर सवाल उठते रहेंगे और जवाब के लिए समय का इंतजार करना होगा।

इन तमाम सवालों से पहले बांग्लादेश में जो घटनाक्रम घटित हुआ उसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्?तीफा दिया। सेना की मदद से ही शेख हसीना अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ ढाका से सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए भारत पहुंचीं और यहां से वो लंदन रवाना होने के लिए प्रयासरत हैं। यह पहला अवसर नहीं है कि शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी है, बल्कि इससे पहले 1975 में भी उन्होंने अपनी बहन के साथ भारत का रुख किया था। तब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी जिसने उन्हें राजनीतिक शरण देने का काम किया था। तब शेख हसीना करीब 6 साल भारत में गुजारे थे। दरअसल 15 अगस्त 1975 को शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की उनके निवास पर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यह वह काला दिन था जबकि शेख हसीना के परिवार के करीब 17 लोगों की हत्या की गई थी। इस खूनी हमले से शेख हसीना और उनकी बहन इसलिए बच गईं थीं क्योंकि उस समय वो जर्मनी में थीं।

बहरहाल बांग्लादेश के एक बार फिर हालात बिगड़े हैं और इसी बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वेकर उज जमान ने ऐलान किया है कि सेना ने देश की कमान संभाल ली है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत का रास्ता खुले होने की बात कही है। सेना प्रमुख हर मसले का हल बातचीत से निकालने का आव्हान भी करते दिखते हैं। वो कहते हैं कि इस हिंसा और विरोध प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उन्होंने अराजकता खत्म कर, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की बात भी कही। बहरहाल राजनीतिक पकड़ मजबूत करने देश को संभालने और लोगों का विश्वास जीतने उन्होंने राष्ट्रपति से चर्चा कर एक अंतरिम सरकार बनाए जाने का भी ऐलान कर दिया है। इसी बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आए हैं।

यह समझने वाली बात है कि सेना प्रमुख जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि देश में इस समय कर्फ्यू या आपातकाल लगाने की आवश्यक्ता नहीं है। रातों-रात समस्या का समाधान निकालने की बात भी की जा रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं यह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पदच्युत करने की साजिश का हिस्सा तो नहीं था, जिसमें पूरी सरकार ही फंस गई। इतिहास दोहराने जैसा काम भी यह लगता है। बहरहाल प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे चुकीं है और अंतरिम सरकार बहुत जल्द बना ली जाएगी। ऐसे में कामना की जा सकती है कि बांग्लादेश के हालात बहुत जल्द सामान्य हो जाएंगे, जो कि पड़ोसी देश के लिए भी सही ही होंगे। क्योंकि पड़ोसी मुल्क की आग सीमा पार कब कर जाए कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में हालात पर नजर रखते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता भी है। भारत सरकार ने सीमा पर इसका पुख्ता इंतजाम कर रखा है। इसलिए ज्यादा चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन घुसपैठियों से निपटना वाकई एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जब संकट में फंसे लोग जान बचाने देश छोड़ सीमा पार करते हैं तो इनकी आड़ में बड़ी संख्या में आतंकवादी भी बॉर्डर क्रॉस कर उत्पात मचाने से बाज नहीं आते हैं। यह भारत के साथ पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक की सबसे बड़ी समस्या रही है। इस पर नकेल कसने के लिए सीमाओं पर बारीक नजर रखने और जवानों की और तैनाती करने की यदि आवश्यकता आन पड़ती है तो वह भारत सरकार को करना होगा। चूंकि अभी जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद ने फिर से सिर उठाया हुआ है, ऐसे में बांग्लादेश की समस्या भारत के लिए भी मुसीबत साबित हो सकती है। इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहां कहना गलत न होगा कि भारत दुनियां का एकमात्र विश्वबंधुत्व के साथ सर्वेभवन्तु सुखिनः का मंत्र फूंकने वाला देश है, जिसके प्रयासों से विश्वयुद्ध की आंशकाओं को टाला भी जा सकता है। संभवतः यही वजह है कि दुनियां के तमाम देशों की नजरें इस समय भारत पर टिकी हुई हैं।

संपादकीय

घटेगी वक्फ की ताकत

वक्फ बोर्ड की ताकत घटाने और उसे नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन का केंद्र सरकार का फैसला साहस भरा कदम है। निकट भविष्य में वक्फ बोर्ड. पहले की तरह किसी भी संपत्ति को स्वेच्छा से अपनी संपत्ति नहीं घोषित कर पाएंगे। कैबिनेट ने 40 संशोधन को मंजूरी दी है। साफ है सरकार वक्फ बोर्ड. की मनमानी पर सख्ती के मूड़ में है। स्वाभाविक तौर पर सरकार के इस फैसले पर सियासी तनातनी और सरगर्मी भी तय है। कई मुस्लिम संगठन सिफारिश के विरोध में आ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का तर्क है कि सरकार वक्फ बोर्ड. की स्वायत्तता छीनना चाहती है, जो धर्म की आजादी के खिलाफ है। यही वजह है कि इसमें सियासी बढ़त के लिए संशोधन पेश करने से पहले भाजपा अपने सहयोगियों को साधने में जुट गई है। इसके लिए उसे जोर-आजमाइश ज्यादा करनी होगी। गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड अधिनियन 1954 में पारित हुआ था। इसके बाद इस अधिनियम में समय के अनुसार कई संशोधन किए गए। नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी थी। लाजिमी है कि कांग्रेस के साथ उसके सहयोगी पार्टियां सरकार के इस प्रस्ताव से इत्तेफाक नहीं रखती। वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने दिसम्बर 2022 में इसके बारे में लोक सभा में जानकारी दी थी। कहा जाता है कि रेलवे और सेना के बाद देश में संपत्ति के मामले में वक्फ तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति मालिक है। हालांकि, सबसे अधिक विवाद वक्फ के अधिकारों को लेकर है। क्योंकि वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में इस बात पर जोर दिया गया है कि बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ बोर्ड. निरंकुश हो गया और इसकी कार्यशैली पर लगाम लगाने की महती जरूरत भी है। दरअसल, वक्फ का निर्माण पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए किया गया था, लेकिन इसका सही से उपयोग नहीं किया गया, बल्कि दुरु पयोग ज्यादा किया गया। वक्फ की अरबों की संपत्ति अवैध रूप से कुछ लोगों के कब्जे में हैं, महिलाओं की भागीदारी इसमें न के बराबर है। इन सारी अनियमितताओं पर अगर सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है तो उसके फैसले को समर्थन देने में किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिक नफा-नुकसान के तराजू पर तौलने से पहले सभी राजनीतिक दलों को हफ्ते भर बाद संसद में पेश किए जाने का इंतजार करना चाहिए। हां, बिना-वजह बयानबाजी कर माहौल खराब करने से हर किसी को बचने की जरूरत है।

चिंतन-मनन

'थुकदम' पर शोध खोलेगा जीवन-मृत्यु का रहस्य

गीता में कहा गया है कि शरीर तो एक पुतला मात्र है इसमें मौजूद आत्मा जीव है। यह जिस शरीर में होता है उस शरीर के गुण, कर्म और अपेक्षा के अनुरूप मृत्यु के बाद नया शरीर धारण कर लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है और न इसकी मृत्यु होती है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब-तक शरीर जीवत रहता है। आत्मा द्वारा शरीर का त्याग करते ही शरीर सड़ने लगता है और इससे बदबू आने लगती है। गरूड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी काफी समय तक आत्मा शरीर के आस-पास भटकती रहती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है और उनका मोह शरीर से लगा रहता है उनकी आत्मा को यमदूत जबरदस्ती खींचकर ले जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में योगी मुनि अपनी इच्छा से योग द्वारा शरीर का त्याग करते थे।

माना जाता है कि इस प्रकार शरीर का त्याग करने से सद्गति प्राप्त होती है। हिन्दू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में भी ऐसी ही मान्यता है। इसलिए बौद्ध भिक्षु भी योग द्वारा शरीर त्याग किया करते थे। योग द्वारा शरीर का त्याग करने से शरीर जल्दी दूषित नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवन का अंश मौजूद रहता है। हाल ही में धर्मशाला स्थित डेलेक अस्पताल में बौद्ध भिक्षु गैंगिंग खेतरुल रिंपोंछे की मौत के छह दिन बाद भी उसके पार्थिव शरीर के सुरक्षित रहने से दुनिया भर के चिकित्सक हैरान हैं। हालांकि इससे पूर्व जनवरी 2013 में भी दक्षिण भारत की ड्रेपुंग मोनेस्ट्री में इस तरह का मामला सामने आया है, जिसमें मोनेस्ट्री के प्रमुख रहे लोबसंग निमा मौत के बाद 18 दिन तक इसी अवस्था में रहे थे। इन घटनाओं ने मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति की मान्यताओं पर एक नयी बहस छेड़ दी है और शास्त्रों एवं पुराणों की मान्यताओं पर पुनः अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया है।

उमंग व उल्लास का पर्व है तीज

रमेश सर्राफ धमोरा

श्रावण में वर्षात के मौसम में चारों ओर हरियाली की चादर सी बिखर जाती है। जिसे देख कर सबका मन झूम उठता है। सावन का महिना एक अलग ही मस्ती और उमंग लेकर आता है। श्रावण के सुहावने मौसम के मध्य में आता है तीज का त्यौहार। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं। उत्तर भारत में यह हरियाली तीज के नाम से भी जानी जाती है।

सावन के महीने में सिंजारा, तीज, नागपंचमी एवं सावन के सोमवार जैसे लोकपर्व उत्साह पूर्वक मनाए जाते हैं। श्रावण के महीने में मनायी जानेवाली हरियाली तीज आस्था, प्रेम, सौंदर्य व उमंग का त्यौहार है। तीज को मुख्यतः महिलाओं का त्यौहार माना जाता है। यह पर्व महिलाओं की सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रतीक है। सावन माह में मनाया जाने वाला हरियाली पर्व दंपतियों के वैवाहिक जीवन में समृद्धि, खुशी और तरक्की का प्रतीक है। तीज का त्यौहार भारत के कोने-कोने में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के उत्तरी क्षेत्र में हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाता है।

वर्षा ऋतु में श्रावण के महीने में हमारे देश में चारों तरफ पानी बरसता रहता है। इस दौरान चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। हरियाली के आगोश में प्रकृति इस तरह झूम उठती है मानो पृथ्वी अपनी हरी-भरी बाहें फैलाकर सबका अभिनंदन कर रही हो। श्रावण के महीने को हिंदू धर्मावलंबी भगवान शिव का महीना मान मानकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। कावड़िए देशभर में विभिन्न नदी, तालाबों से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। गणगौर के बाद त्योहारों का सिलसिला रुक जाता है वह एक बार फिर श्रावण मास की तीज से प्रारंभ हो जाता है। श्रावण का महीना महिलाओं के लिए विशेष उल्लास का महीना होता है। इस महीने में आने वाले अधिकांश लोक पर्व महिलाओं द्वारा ही मनाए जाते हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था। परिणामस्वरूप भगवान शिव ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। माना जाता है कि श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन माता पार्वती ने सौ वर्षों के तप उपरान्त भगवान शिव को पति रूप में पाया था। इसी मान्यता के अनुसार स्त्रियां माता पार्वती का पूजन करती हैं।

श्रावण का आगमन ही इस त्यौहार के आने की आहट सुनाने लगता है। समस्त सृष्टि सावन के अदभूत सौंदर्य में भिगी हुई सी नजर आती है। यह पर्व भारतीय जनमानस के अटूट विश्वास को और अधिक प्रगाढ़ता प्रदान करने का पर्व है। इस पर्व में हरियाली शब्द से ही साफ है कि इसका ताल्लुक पेड़-पौधों और पर्यावरण से है। यह त्योहार जीवन में जश्न का प्रतीक है और हरियाली तीज का पर्व प्रकृति का त्योहार हैं। इस मौके पर महिलाएं अच्छी फसल के लिए भी प्रार्थना करती हैं। तीज पर मेहंदी लगाने, चूडियां पहनने, झूला झूलने तथा लोक गीतों को गाने का विशेष महत्व है। तीज के त्यौहार वाले दिन खुले स्थानों पर बड़े-बड़े वृक्षों की शाखाओं पर, घर की छत पर या बरामदे में झूले लगाए जाते हैं जिन पर स्त्रियां झूला झूलती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेलों का भी आयोजन होता है।

हाथों में रची मेंहदी की तरह ही प्रकृति पर भी हरियाली की चादर सी बिछ जाती है। इस नयनाभिराम सौंदर्य को देखकर मन में स्वतः ही मधुर झनकार सी बजने लगती है और हृदय पुलकित होकर नाच उठता है। इस समय वर्षा ऋतु की बौछारें प्रकृति को पूर्ण रूप से भिगो देती हैं। सावन की तीज में महिलाएं व्रत रखती हैं। इस व्रत को अविवाहित कन्याएं योग्य वर को पाने के लिए करती हैं तथा विवाहित महिलाएं अपने सुखी दांपत्य की चाहत के लिए करती हैं।

राजस्थान में जिन कन्याओं की सगाई हो गई होती है। उन्हें अपने होने वाले सास ससुर से एक दिन पहले ही भेंट मिलती है। इस भेंट को स्थानीय भाषा में सिंझारा कहते हैं। सिंझारा में मेंहदी, लाख की चूडियां, लहरिया नामक विशेष वेश-भूषा, घेवर नामक मिठाई जैसी कई वस्तुएं होती हैं। पीहर पक्ष द्धारा अपनी विवाहित पुत्री को भी सिंजारा भेजा जाता है। जिसे पूजा के बाद सास को सुपुर्द कर दिया जाता है। राजस्थान में नवविवाहिता युवतियों को सावन में ससुराल से मायके बुलाने की भी परम्परा है।

तीज के अवसर पर नवयुवतियां हाथों में मेंहदी रचाते हुए गीत गाती हैं। समूचा वातावरण शृंगार से अभिभूत हो उठता है। इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता है कि महिलाओं का हाथों पर विभिन्न प्रकार से बेलबूटे बनाकर मेंहदी रचाना। राजस्थान में हाथों व पांवों में भी विवाहिताएं मेंहदी रचाती हैं। जिसे मेंहदी मांडना कहते हैं। इस दिन राजस्थानी बालाएं दूर देश गए अपने पति के तीज पर आने की कामना करती हैं। जो कि उनके लोकगीतों में भी मुखरित होता है। राजस्थान के गांवों में पहले लड़किया गुड्डे-गुड्डी का खेल खेलती थी। तीज के दिन से गुड्डे-गुड्डी का खेल खेलना बन्द कर देती थी। इसलिये गांव की लड़किया एक साथ एकत्रित होकर अपनी पुरानी गुड्डे-गुड्डी को गांव के पास के नदी,तालाब, जोहड़ में बहा देती थी। जिसे गुड्डी बहावना कहा जाता था।

अपने सुखी दांपत्य जीवन की कामना के लिये स्त्रियां यह व्रत किया करती हैं। इस दिन उपवास कर भगवान शंकर-पार्वती की बालू से मूर्ति बनाकर शोडशोपचार पूजन किया जाता है जो रात्रि भर चलता है। स्त्रियों द्धारा सुंदर वस्त्र धारण किये जाते है तथा घर को सजाया जाता है। इसके बाद मंगल गीतों से रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत को करने वालि स्त्रियों को पार्वती के समान सुख प्राप्त होता है। तीज का आगमन वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही आरंभ हो जाता है। आसमान काले मेघों से आच्छादित हो जाता है और वर्षा की फोहार पड़ते ही हर वस्तु नवरूप को प्राप्त करती है। ऐसे में भारतीय लोक जीवन में हरियाली तीज या कजली तीज महोत्सव का बहुत गहरा प्रभाव देखा जा सकता है।

उत्तराखंडः आवाजाही से बढ़ रही तबाही

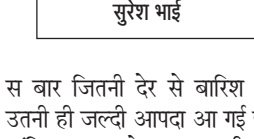

सुरेश भाई

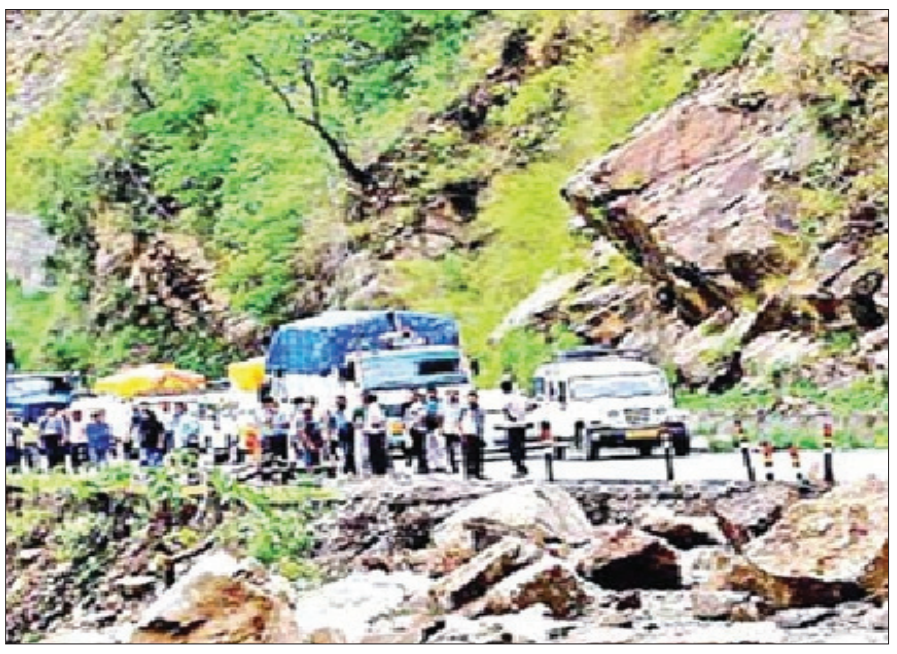

इस बार जितनी देर से बारिश शुरू हुई है। उतनी ही जल्दी आपदा आ गई है। जुलाई के अंतिम सप्ताह से चारधाम की सड़कें ध्वस्त होने लगी है। आवागमन के पैदल रास्ते भी नदी में समा रहे हैं। जहां-जहां मनुष्य के कदम पड़ रहे हैं वहां धरती इतनी संवेदनशील बन गई कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। ध्यान रहे कि चारधाम बरसात में सुरक्षित नहीं है।

सुरक्षा के नाम पर जितनी भी घोषणाएं करें वह मौसम के सामने बौनी पड़ रही है। यहां हर साल आपदा की भवावहता बढ़ती ही जा रही है। केदारनाथ आपदा की तरह ही मंदाकिनी नदी में इस बार फिर से जल प्रलय जैसा रूप लोगों ने देखा है। स्थिति इतनी विकराल बन गई कि 2 अगस्त तक केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे लगभग 4000 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से लगभग 700 यात्रियों को हेली सेवा से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मंदाकिनी नदी में जल स्तर बढ़ने से पैदल मार्ग पर रामवाड़ा में दो पुल और भीम बली में 25 मीटर रास्ता क्षतिग्रस्त होकर बह गया था, जहां से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को मुश्किल से बचाया जा सका है। पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। यदि पहले मौसम के अलर्ट की सूचना पर ऋषिकेश में ही यात्रियों को जाने से रोक देते तो समय और खर्च दोनों भी रोका जा सकता था। उत्तराखंड और हिमाचल में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 16 लोग उत्तराखंड में मलबे में दबकर मरे हैं। हिमाचल में 6 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 53 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक वहां पर 300 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। 2023 की आपदा में भी हिमाचल में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ था और लगभग 500 लोग मारे गए थे। इस बार अभी तक यहां दो पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गए हैं, जिसके कारण दर्जनों लोग लापता है। आपदा की यह जानलेवा घटना कुल्लू, मंडी और रामपुर में अधिक हुई है। हिमाचल की 445 सड़कें यातायात के लिए ठप पड़ी है। जिसको खोलने के लिए राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले पर्यटकों ने आपदा की स्थिति को देखकर अपनी बुकिंग कैंसिल की है, जिसके कारण पर्यटन कारोबार पिछले वर्ष की तरह प्रभावित हो गया है। कुल्लू-शिमला की सीमा पर समेज खड में आई बाढ़ में लगभग 36 से ज्यादा मकान बह गए हैं। यहां ६ बच्चों समेत 36 लोग भी लापता हैं। 7 घंटे में सामान्य से 305 मिलीमीटर ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लगभग 7 पुल बह गए हैं। सतलुज और ब्यास नदियों का जलस्तर खतरे के करीब पहुंचने लगा है। यहां पर श्रीखंड महादेव मार्ग पर करीब 250 लोग फंसे रहे। चिंता की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं सबसे अधिक विनाश का कारण बन रही हैं। 2013 की केदारनाथ आपदा के समय भी 24 जल विद्युत परियोजनाओं ने मंदाकिनी और अलकनंदा घाटी का जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित किया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इसकी पुनरावृत्ति फिर से देखी जा रही है। जिला टिहरी गढ़वाल में बालगंगा और धर्मगंगा पर 26-27 जुलाई की भीषण बाढ़ ने जो विनाश लीला सामने लाई है; उसने केदारनाथ आपदा की याद ताजा की है। यहां पर तीर्थ यात्रियों के लिए प्रसिद्ध बूढ़ा केदारनाथ का मंदिर भी है, जिसके दोनों तरफ ये नदी बहती है। यहां 20 किमी के क्षेत्र में नदी तटों पर निर्माण कार्यों से एकत्रित मलवे के बहने से पैदा हुए भीषण जल प्रलय से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हुई है। लोगों के होटल, मकान, गौशालाएं नदी में समा गए। यहां पर बड़े बांध के विकल्प के रूप में 50 किलोवाट की एक छोटी पण बिजली बनाई गई थी, जो पूरी तरह मलबे में दब गई है। इससे आगे भी तीन मेगावाट की एक लघु जल विद्युत भी ध्वस्त हो गई हैं। क्षेत्र के एक दर्जन पुल जर्जर हो चुके हैं। तिनगढ़ गांव के परिवारों के घरों में मलवा जमा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और राहत और पुनर्वास का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इन नदियों के दोनों तरफ लोग पूर्व में आपदा से प्रभावित हुए श्रीनगर, उत्तरकाशी और केदारनाथ की तर्ज पर पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं क्योंकि यहां हालात बहुत चिंताजनक हैं।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Have you come across the TikTok viral #eyebrowblindness trend Learn what MUAs have to say

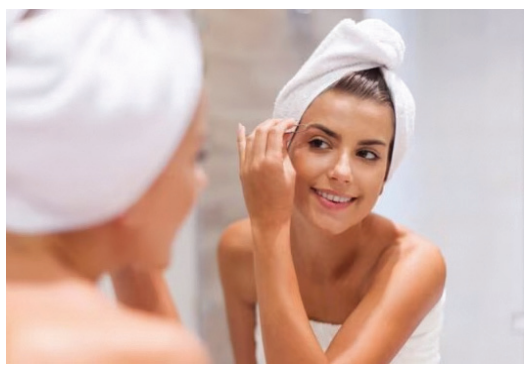

The Internet is always celebrating one trend or the other, be it dewy skin, glossy lips or rosy cheeks. Once again, eyebrows are under the spotlight, and this time, it's not for a good cause. This recent trend going viral on TikTok has people recounting their eyebrow-shaping experiences throughout the years- while some cringe at their boxy, or soap-feathered brows, others regret having jumped on the bandwagon instead of understanding their face shape.Indianexpress.com spoke to makeup artists to understand their take on the viral #eyebrowblindness trend and found out what people should keep in mind when it comes to getting their brows done henceforth."Eyebrow blindness is the unawareness or lack of understanding about the importance of properly grooming and maintaining one's eyebrows. We are not against eyebrow grooming practices such as shaping or microblading. However, it is crucial to be mindful when choosing a technician," said Sneha Charan, Founder of The Top Knot Makeup Studio, Lucknow.Ensure you check the quality of the products used, maintain proper hygiene, and receive a thorough consultation on the appropriate shape of eyebrow and how it suits your face structure," she said."This trend will certainly see a change in the audiences mindset. Content creators will also have to be conscious of what they would like to give to their community. Followers are now going to start, at a very subconscious level, to think if this is really what they need to add to their beauty and then take a call on following it," shared Preeya, makeup artist and Co-Founder of Tvesate.According to her, this viral trend is going to ignite that consciousness in people to ensure they don't have to fall prey to everything that is happening on a digital platform.

Is it safe to follow eyebrow trends?

"Eyebrows have changed shapes through every single decade. Thin brows of the 00's moved to thick defined brows in the 10's and later moved to feathery brows. Most of these trends have come back from the retro times as well. As long as the person trying the trend is mindful of the change it can give them and is fully cognizant of whether it suits them or not, then it's absolutely ok to try," shared Preeya.The key is to be in full understanding of your own style preference and take guidance from a professional or an expert, she added.Agreeing with Preeya, Charan shared that when in doubt, seek guidance from a professional makeup artist or dermatologist. They can recommend safe products and techniques and provide advice tailored to your specific

skin type and needs.Before trying any trend, do some research to understand its origins, safety considerations, and the experiences of others who have tried it. This can help you make an informed decision and avoid potential pitfalls," she said.Charan advised that not every trend will suit everyone. "It's important to embrace your unique features and preferences. Don't feel pressured to follow trends just because they are popular; choose what makes you feel comfortable and confident," she added.

Hard questions before Sri Lanka's presidential poll

Sri Lanka has experienced unprecedented hardships in the past two years. There has been political and economic turmoil. Do voters actually trust the 'normalcy' presented as the reality?

Political battle lines are being drawn as Sri Lanka prepares to elect the country's 10th executive president on September 21. The election secretariat will accept nominations on August 15 for one of the toughest political battles, the first to be held after the island's economic collapse.

The government has played coy for long, employing delaying tactics despite elections being due. First, the local authorities' elections due in 2023 were postponed citing lack of funds. Next, a fundamental rights petition that sought an order to halt a presidential election until the Supreme Court delivers its interpretation on the date of the presidential poll was dismissed by a five-member bench. The government recently introduced the 22nd Amendment to the Constitution, viewed as a blatant attempt to postpone polls. Days ago, the government suffered a significant setback when court granted leave to proceed for nine FR petitions that challenged the appointment of an IGP without due process and issued an interim order restraining him from functioning as IGP.There is a massive gulf between 2020 and the 2024 elections. Gotabaya Rajapaksa rode a wave of nationalistic hype to be elected in 2020. This enthusiasm was swiftly doused when the island was hit by an unprecedented financial crisis, the worst in post-independence. The crashing economy brought other concerns to the fore; food, fuel, electricity, essential drugs, fertiliser and livelihoods, quickly replacing the nationalistic fervour with daily needs.Despite the increasing popularity of the left-leaning National Peoples' Power (NPP), there's little hype around the 2024 polls. People are expected to elect a president who can redeem the debt-strapped island from the damning state of bankruptcy, a leader with foresight and the capacity for course correction. The prospects before them don't augur well.

At present, Sri Lanka is currently on survival mode, staying afloat thanks to a bailout from the International Monetary Fund (IMF). This has allowed a false sense of normalcy to prevail and lull a section of the island's urban middle class, following President Wickremesinghe's success in securing a debt restructuring agreement. The crisis president was elected by the parliament to serve the remaining period of Rajapaksa's term.The main contenders at the forthcoming polls will be President Ranil Wickremesinghe, opposition leader Sajith Premadasa and Anura Kumara Dissanayake, who leads the NPP. A former army commander and a 2010 presidential candidate Sarath Fonseka and Minister of Justice Wijeyadasa Rajapakshe too have joined the fray. Fonseka was a member of Premadasa's Samagi Jan Balawegaya (SJB) and Rajapakshe until last week served on Wickremesinghe's cabinet. The Sri Lanka Podujana Peramuna that swept into power just four years ago found their political fortunes dwindling. In the face of economic hardships, people quickly turned against the Rajapaksas and brought them down, which increased ground support for the NPP.

Wickremesinghe is both credited and criticised at the same time for securing emergency support for Sri Lanka through effective negotiations with multilateral lenders and China, to buy Sri Lanka a breather. However, his neoliberal economic policies are trusted only by some but are critiqued for not containing a long-term solution. They fault the 'fixing method' for perpetuating debt, increased loss of livelihoods, crippling taxation driving brain drain, crippling austerity measures, increasing poverty and food inflation, while no plans are afoot to increase investments, exports and revolutionise the economy. Even those aligned with his economic policies are perplexed by his authoritarian streak, not only in cracking dissent but also the suffocating taxation.

Over time, NPP's Anura Dissanayake has emerged as the island's most popular political figure. The party's popularity soared along with the 2022 public agitations that saw President Rajapaksa being forced to quit. There is also sizeable support for Premadasa and the SJB, making it a tripartite contest.

While Sri Lankan voters are known for electing people on the basis of class, ethnicity, religion, caste and old loyalties or rhetoric, it is evident there is voter fatigue. People are tired of voting the political elite in cycles to gain the same outcome. There is increasing support for a political change among many people, to break the two-party cycle. While some express their desire for stability and conservative choices, others look for a political overhaul and a course correction. Only the coming weeks will show how these two camps increase their support base.

But the choice before the voters this September is beyond a matter of popularity—or even ideology. It will have to rest in realism. This choice, despite the bleak options available, will decide the future of Sri Lanka. The political establishment too has been notified that people's aspirations need to be aligned to secure a mandate. This makes it that much difficult for a single party to muster a simple majority.

Sri Lanka has experienced unprecedented hardships in the past two years. There had been political and economic turmoil. Do voters actually trust the 'normalcy' presented as the reality? Are they prepared to be hit by another financial shock soon, and to have this bubble burst, as it would? Are people ready to bear more taxes and food inflation as the painful IMF road is traversed?

The question will be, do people accept the current status quo? Or are Sri Lankans ready for a political overhaul and going through hard times (an easy prediction) for an economic, socio-political reset, which is what the NPP is offering? Do people know what formula may actually work for the island and make a genuine contribution towards economic building? If the choice is different and an overhaul, this would call for more sacrifices by the people. Is the nation ready? What will be the nation's answer to debt servicing and pivoting economic growth, the twin monumental tasks before any future leader?

J&K at a crossroads

Five years after Art 370 abrogation, challenges persist

IT's been five years since the Centre took the landmark decision to abolish Article 370 and bifurcate the state of Jammu and Kashmir into two union territories. According to the government, the reorganisation was aimed at 'fully integrating' J&K and Ladakh into the national mainstream and ensuring that the people of these UTs were not deprived of constitutional rights and benefits of Central laws that were being enjoyed by residents of other parts of the country. The ruling BJP has often showcased the abrogation as the panacea for all ills plaguing J&K, but things have not turned out that way. The state-turned-UT finds itself at a crossroads today, awaiting the restoration of statehood as well as the resumption of Assembly elections.In December last year, the Supreme Court had upheld the constitutional validity of the decision to abrogate Article 370, giving the Centre a leg up months before the Lok Sabha polls. At the same time, the court had directed the Election Commission of India (ECI) to hold the Assembly elections in J&K by September 30. With this deadline fast approaching, a high-level ECI team is set to visit the region later this week to review poll preparedness. A major challenge for the authorities is to provide a peaceful environment for the electoral exercise amid a spate of terror attacks that have targeted soldiers as well as civilians in recent months. What has added to the anxiety and uncertainty is the reluctance of the government to specify a time frame for restoring statehood, even as the move to grant more powers to the Lieutenant Governor has riled anti-BJP parties.The Centre is making efforts to put J&K on the path of all-round development, but cross-border terrorism and the failure to take the regional political leadership along continue to obstruct the course of long-term peace and normalcy. Having all stakeholders on board is a must to herald a new dawn in the troubled region.

What is a 'privileged Dalit'? Creamy Layer definition cannot just be economic

The recent judgment of the Supreme Court regarding sub-classification among SC and ST groups vis-a-vis granting reservation raises a more fundamental question. Why do we need reservation for Dalits? I would like to share a snippet from my experience of living with caste.I lived in a rented accommodation as a student in Delhi University. One day, tired of Delhi's water woes, I asked my landlady if I could call somebody and get our water tank cleaned. Unsurprisingly, my landlady replied, "Ab C***r (using a term for members of the Jatav community) tanki mein jayenge aur hamare pani ko ganda karenge?" I was quick to remind her that she used a Dalit's rental money to run her house, yet she thought our touch would "pollute" her water tank. But money, I learnt, is beyond the pale of purity and pollution. And in this instance, money did help me get accommodation — but it stripped me of my dignity.

While caste-based reservation was not meant to be an indefinite constitutional guarantee given by B R Ambedkar to Dalits, it is the most important tool for the social empowerment for the most marginalised. One can argue that there is a need to revisit reservations in the context of changing caste dynamics. And the thought behind the Supreme Court's verdict is noble. However, the question of implementation remains.How do we define who is most marginalised among the marginalised? What are the parameters we intend to put in place to measure marginalisation? Reservation was meant to abolish "untouchability and provide access to justice". The manifestation of untouchability has changed from its physical aspects to more intangible forms. Why are a majority of applicants for academic posts under the SC/ST category declared as "not found suitable"? How many law firms or chartered accountant firms are owned and run by the SC and ST communities? And why do we still have reported cases of deaths from manual scavenging in the country, though the practice has been constitutionally abolished?

Why did a Dalit IPS officer still need police protection to ride a mare as part of a procession in his village in Haryana as recently as 2022? Reservations should eradicate caste-based discrimination and none among us will disagree that its benefits should trickle down to the ones who need it the most. In the absence of a clear manual to define the most marginalised, this reform could well end up being manipulated at the state level for electoral and political numbers.The judgment on the issue by a seven-judge bench in State of Punjab v. Davinder Singh, which affirmed sub-categorisation among SCs, took place in a broader context. Globally, there has been a rise in conservatism, especially in relation to affirmative action. The US Supreme Court in June 2024 held that race-based affirmative action in higher educational institutions was illegal. The promise of reservations for Dalits in India was that of equality, dignity and justice. This recent judgment made me introspect on whether economic parity puts me on the same pedestal as my fellow upper-caste colleagues. But, tragically, marginalisation is more complex than that: It has a spectrum of privileges and disadvantages experienced by individuals within a society. Marginalisation manifests in various forms, and it is imperative to account for these parameters when assessing and addressing issues of privilege and exclusion to ensure a more equitable approach, rather than reducing it to economic status.

From a social justice perspective, economic progress does not take away the indignity faced by a so-called "privileged Dalit". Sub-classification per se is not bad. However, in India today, it seems to be in direct conflict with the inherent idea and goal of social inclusion. In my experience, mere economic advancement does not guarantee social mobility. We need to ask ourselves: Have our personal spaces in society become safer, more inclusive, and devoid of caste discrimination? No targeting and exclusion of the creamy layer is possible without a caste survey with targeted data collection. We need to charter a discourse based on empirical and anthropological data of every community. What are the defining parameters which the state will use to determine empirical evidence of the progress of Dalits and who belongs to the creamy layer?States need to do a comprehensive empirical evidence collection and statistical evaluation of substantial data. However, this data collection should not be a mere analysis of the economic advancement and progress of a particular Dalit community. That would be an incomplete analysis.Affirmative actions were envisioned as a mechanism that could provide a level playing field to these communities in the social institutions of education and employment. It was ammunition to help provide political representation, recognise their oppression, redistribute intellectual resources, and social rehabilitation, ultimately resulting in better social standing for these communities. It was aimed at dismantling the structural and generational privilege that facilitates caste-based discrimination and determines access to a better life.Reservation was a tool to acquire social equity, which was correctly thought to be the precursor to social equality. The facilitation of the acquisition of skills, knowledge, and social connections that would eventually lead to the upward social mobility of oppressed communities were the key factors promoted by reservation policies. It would do well for us to remember that reservation challenges the total hegemony of dominant factions in the society, and what the dilution of this principle would mean for those who continue to be oppressed.

Indian gold industry launches self-regulatory organisation for excellence

Supported by the World Gold Council, IAGES aims to increase transparency and trust in the Indian gold sector.

MUMBAI. The Indian gold industry announced the formation of the Indian Association for Gold Excellence and Standards (IAGES) on Tuesday. This new self-regulatory organisation (SRO) is supported by the World Gold Council (WGC) and aims to remove the trust deficit and enhance transparency within the sector.The framework for IAGES will be independently governed and professionally managed, with its release expected soon, followed by the announcement of memberships. According to WGC Regional CEO, India, Sachin Jain, the organisation is expected to become operational by December this year or January 2025.IAGES will be established by national industry associations, including the Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA), the All India Gems and Jewellery Council of India (GJC), and the Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC)."IAGES, created by the Indian gold industry, represents the coming together of various stakeholders in the sector. It aims to increase consumer and government confidence by enhancing trust in the Indian gold industry through the adoption of fair, transparent, and sustainable practices, regulatory compliance, establishing a code of conduct, and introducing an audit framework across the entire value chain," Jain added.GJEPC Chairman Vipul Shah commented, "The formation of IAGES is a landmark achievement for the Indian gold industry. It underscores our collective commitment to establishing the highest standards of ethics, transparency, and sustainability."GJC Chairman Saiyam Mehra stated, "Together, we aim to promote best practices, ensure the highest quality, and foster trust among consumers and industry stakeholders.""IAGES is poised to not just fortify India's standing as a global gold hub but also catalyze innovation and progression within the sector," added IBJA National President Prithviraj Kothari.The Indian gold industry is hopeful that IAGES will play a crucial role in enhancing the credibility and reliability of the sector, thereby benefiting all stakeholders involved.

Akums Drugs and Pharmaceuticals IPO lists at 7% gain: Book profit or sell

New Delhi. Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited had a modest debut on the stock market, with its shares listing at a premium of only 7% on the National Stock Exchange (NSE).The shares began trading at Rs 725 on the NSE, reflecting a 6.77% premium above the issue price of Rs 679. The same opening price of Rs 725 was seen on the Bombay Stock Exchange (BSE).

The company's initial public offering (IPO) was launched for subscription on July 30, with a target to raise Rs 1,856.74 crore. The IPO had a price range set between Rs 646 and Rs 679 per share.The IPO comprised a fresh issue of 1 crore shares valued at Rs 680.00 crore, along with an offer for sale of 1.73 crore shares worth Rs 1,176.74 crore.Prashanth Tapse, Senior VP (Research), Mehta Equities Ltd said that even though Akums Drugs listing was below street expectation, we continue to believe and hold our long term positive outlook in the India's largest CDMO player by revenue, production capacity and client base.

"On a valuation parse post listing is still in comfortable zone to "HOLD" Akums Drugs and Pharmaceuticals ltd IPO for a long term perspective. We believe the market can give Akums a premium multiple towards its leadership position which may result in delivering healthy post listing gains on its issue price," said Tapse.Shivani Nyati, Head of Wealth, Swastika Investmart Ltd said that Akums Drugs and Pharmaceuticals, a prominent CDMO player, made a subdued debut on the stock market, listing at Rs. 750 per share, reflecting a modest 10% gain over its issue price of Rs. 679.

"While the IPO received a strong subscription of 63.44 times and the initial market buzz was positive, the actual listing fell short of expectations, likely influenced by the prevailing market volatility," she said.

"The company's strong fundamentals and market position offer potential for long-term growth, but investors should carefully assess the risks and market volatility. Investors with a long-term view may hold their position by keeping a stop loss at its issue price," said Nyati.

Government unlikely to relax Rs 32,000 crore tax demand on Infosys: Report

New Delhi. The government is not considering any relaxation on the Rs 32,000 crore tax demand issued to Infosys, reported Reuters, quoting a government source.The demand, made under the Goods and Services Tax (GST) regulations, has prompted Infosys, the country's second-largest IT services firm, to request ten days to respond after meeting with tax officials, the source added.The controversy over Infosys' GST liabilities began when the Karnataka government issued a notice claiming the company owed Rs 32,000 crore in Integrated GST (IGST) under the reverse-charge mechanism for services provided by its foreign branches from FY18 to FY22.The revenue department's stance was that expenses incurred by overseas branches were payments for services rendered to the Indian entity.However, this interpretation was contentious, as experts argued that it implied reimbursements for expenses could be considered payments for services, treating foreign branches as separate legal entities from their Indian headquarters.The notice led to an outcry from the IT industry and experts, with the National Association of Software and Service Companies (Nasscom) criticising it for misunderstanding the IT industry's operating model.Nasscom highlighted that government circulars based on GST Council recommendations should be respected to prevent uncertainty and negatively impacting India's ease of doing business.They noted that GST enforcement authorities were issuing notices for remittances by Indian head offices to their foreign branches, even in cases where no actual service was provided.The industry argued that this was not a case of 'import of service' and highlighted that courts had previously ruled in favor of the industry under similar circumstances during the service tax regime.The Karnataka High Court quashed the initial notice, and the Supreme Court upheld this decision.

Subsequently, Karnataka state authorities withdrew the GST notice against Infosys but directed the company to respond to the Directorate General of GST Intelligence (DGGI), shifting the oversight of the tax probe to this agency.Experts voiced concers about the potential precedent set by such a large notice, warning that it could lead to more tax demands targeting multinational IT companies.

HUL, Dabur, Suzlon Energy, ICICI Bank: Check brokerage firm Anand Rathi's top stock picks

Brokerage firm Anand Rathi Shares and Stock Brokers has shared some of its top stock picks as volatility continues to impact stocks on Dalal Street.

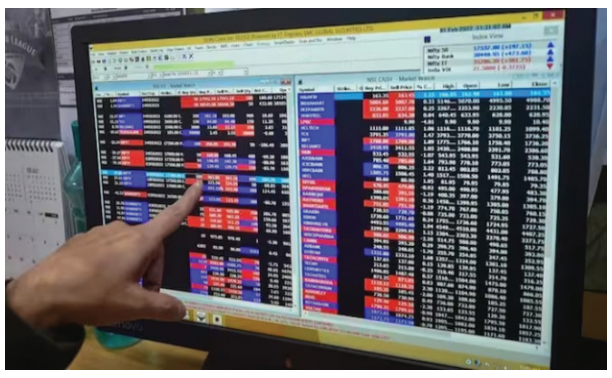

NEW DELHI. Benchmark stock market indices rebounded on Tuesday, marking a decent recovery after crashing in the previous session due to weak global cues.Amid the ongoing uncertainty in stock markets around the world, brokerage firm Anand Rathi Shares and Stock Brokers has exuded confidence in the domestic equity market.

The brokerage firm has shared some of its top stock picks as volatility continues to impact stocks on Dalal Street.For mid-cap and small-cap stocks, they suggest Finolex Cables, HG Infra, NCC, Neogen Chemicals, Sumitomo Chemicals, PNC Infra, Sagar Cements, Senco, Astral, Siemens, Shilchar Technologies, and Suzlon."Domestic theme-related sectors, we believe, will continue to offer an oasis of safety. Therefore, even a complete unwinding of India's carry trade exposure is unlikely to significantly impact the Indian equity market over the long term," said Anand Rathi's Chief Economist and Executive Director Sujan Hajra.

"Any meaningful short-term fall in the Indian equity market should be seen as an opportunity to increase exposure to equity," he added.He also expressed confidence in the Indian markets, stating, "Overall, India's financial sector has become more resilient over the past decade thanks to tighter regulations by the Reserve Bank of India (RBI). The country's substantial forex reserves ($671bn) and robust macroeconomic performance are likely to shield it from the reversal of yen carry trade."

HUL, Dabur, Suzlon Energy, ICICI Bank: Check brokerage firm Anand Rathi's top stock picks

Benchmark stock market indices rebounded on Tuesday, marking a decent recovery after crashing in the previous session due to weak global cues.Amid the ongoing uncertainty in stock markets around the world, brokerage firm Anand Rathi Shares and Stock Brokers has exuded confidence in the domestic equity market.The brokerage firm has shared some of its top stock picks as volatility continues to impact stocks on Dalal Street.For mid-cap and small-cap stocks, they suggest Finolex Cables, HG Infra, NCC, Neogen Chemicals, Sumitomo Chemicals, PNC Infra, Sagar Cements, Senco, Astral, Siemens, Shilchar Technologies, and Suzlon.

"Domestic theme-related sectors, we believe, will continue to offer an oasis of safety. Therefore, even a complete unwinding of India's carry trade exposure is unlikely to significantly impact the Indian equity market over the long term," said Anand Rathi's Chief Economist and Executive Director Sujan Hajra.

"Any meaningful short-term fall in the Indian equity market should be seen as an opportunity to increase exposure to equity," he added.

He also expressed confidence in the Indian markets, stating, "Overall, India's financial sector has become more resilient over the past decade thanks to tighter regulations by the Reserve Bank of India (RBI). The country's substantial forex reserves ($671bn) and robust macroeconomic performance are likely to shield it from the reversal of yen carry trade."

Furthermore, the drawdown of the Nifty is far lower than that of Nasdaq on account of more than 10% appreciation in the yen over short periods," he added.

Marico shares fall over 4% amid Bangladesh political crisis. Here's why

New Delhi. Shares of FMCG giant Marico, known for its Saffola and Parachute brands, fell over 4% on Tuesday.

The decline comes amid political unrest in Bangladesh, a market that contributes significantly to the company's revenue.Nuvama analyst Abneesh Roy said the disruptions caused by the political turmoil in Bangladesh could raise concerns for Marico in the second quarter of the financial year.He added that Marico has the highest exposure to Bangladesh at 11-12% of its consolidated business, indicating that other FMCG companies have minimal exposure.

Despite the current challenges, Roy mentioned that Marico's long-standing presence in Bangladesh, spanning over two decades, should help maintain its competitive edge.In its June quarter results, Marico revealed that the contribution of Bangladesh to its overall international business has been decreasing.

During the June quarter, it's Bangladesh business saw a 10% growth in constant currency, demonstrating resilience and sustained momentum.Marico's regulatory filing indicated that while Bangladesh and Vietnam have shown strong performance, robust growth in the MENA and South Africa regions has diversified the company's international business, reducing its dependence on Bangladesh.

For the June quarter, Marico reported an 8.7% rise in consolidated net profit to Rs 464 crore and a 7% increase in revenue from operations, totalling Rs 2,643 crore.Meanwhile, domestic brokerage Prabhudas Lilladher has downgraded Marico to a hold rating, citing the ongoing turmoil in Bangladesh as a contributing factor.

Lufthansa, Emirates among 10 foreign airlines in trouble over tax dues: Report

New Delhi. The Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence (DGGI) has issued showcause notices to 10 foreign airlines, including British Airways, Lufthansa, Oman Air, Emirates, and Singapore Airlines, for alleged non-payment of taxes totaling Rs 10,000 crore, The Economic Times reported.The notices, sent over the past three days, address unpaid tax dues related to the import of services by Indian branches from their head offices, added the report.According to officials quoted in the report, the airlines are not covered by a June 26 circular concerning the valuation of the supply of import services by a related person when the recipient is eligible for full input tax credit.The circular, cited by Infosys in response to a recent integrated GST demand of Rs 32,000 crore, does not apply to airlines because they deal in both exempt and non-exempt services.

DGGI had previously requested a segregated list of exempt and non-exempt services from the airlines.

Of the 10 airlines, only four provided the list, while the others did not furnish any explanation. The notices cover the period from July 2017, when GST was introduced, to March 2024.A senior official indicated that the overseas headquarters of these airlines provide services such as aircraft maintenance, crew payments, and rentals, which are considered transactions between separate legal entities and are thus subject to GST.The airlines, however, have not paid these taxes.

The investigation began in August 2023, with key executives from the India offices of these airlines summoned in December 2022 and January 2023 to provide explanations and lists of tax-exempt services, noted the ET report.Foreign airlines contended that GST should only be paid on taxable services in India, arguing that the place of service was both the head office and branch office.They also sought intervention from their respective embassies, which raised the issue with the finance ministry, as reported by ET on June 18.

The issue was subsequently referred to the fitment committee under the GST Council, which approved the June 26 circular to clarify the valuation of the "supply of import services" by a related person.

Bangladesh crisis: How trade with India could face major disruptions

New Delhi Bangladesh has been a key ally for India since Sheikh Hasina became Prime Minister in 2009. Her leadership has significantly improved trade and economic relations between the two countries.However, the ongoing crisis in Bangladesh raises concerns about the future of this partnership and its potential impact on India.The Indian finance ministry is closely watching the situation in Bangladesh. Sheikh Hasina's tenure has seen a rise in trade between the two nations, with India enjoying a trade surplus. Her departure could disrupt these gains, affecting the flow of goods and people and possibly halting a potential free trade agreement (FTA) between India and Bangladesh.Under Hasina, Bangladesh has played a crucial role in combating anti-India terrorist groups and has fostered strong economic and cultural ties with India. In the financial year 2023-24, trade between the two countries reached $13 billion.Bangladesh is a major market for India's cotton exports and imports significant amounts of petroleum products and cereals from India. On the other hand, India imports ready-made garments from Bangladesh, contributing $391 million to their trade.Discussions about a fre trade agreement began in October 2023, with the aim of reducing or eliminating customs duties on goods traded between the two nations. This agreement could have boosted Bangladesh's exports to India by up to 297% and India's exports by 172%, according to a World Bank paper. However, the future of these discussions is uncertain with the current political instability in Bangladesh.

Mohit Singla, chairman of the Trade Promotion Council of India, told the Economic Times, "With the kharif harvest very near, the agri export basket of over $1.8 billion could be impacted, with soybean, soya bean meal, animal feed such as wheat residues, onion, and rapeseed being the worst hit."

Ajay Sahai, director general of the Federation of Indian Export Organisations, said, "Internet disruptions have hurt banking transactions, and commodity exporters are worried about exports to Bangladesh through the land border. The next 7-10 days will be crucial."Infrastructure and connectivity projects have been central to strengthening Indo-Bangladesh relations. Since 2016, India has extended $8 billion in credit for the development of road, rail, shipping, and ort infrastructure in Bangladesh.The Akhaura-Agartala cross-border rail link and the Khulna-Mongla Port rail line, inaugurated in November 2023, are expected to improve trade and people-to-people exchanges.Any disruption in these connetions could limit India's access to its Northeast region, which is connected through narrow land corridors. Existing bus routes and agreements for using Chittagong and Mongla ports also face potential risks.In the financial year 2024, India had a trade surplus of $9.2 billion with Bangladesh. Major exports include cotton, coffee, tea, vegetables, vehicles, and electrical machinery.The current unrest has already caused problems such as internet disruptions affecting banking transactions and difficulties in issuing letters of credit, causing concern among exporters, especially in Kolkata.

Given that a significant portion of exports to Bangladesh falls outside the South Asian Free Trade Area (SAFTA) agreement, and most imports from Bangladesh benefit from zero tariffs, the ongoing unrest poses a serious risk to trade dynamics between the two countries. The coming days will be critical in assessing the impact on trade and economic stability in the region.

Temples burnt, houses attacked: How Hindus have become soft targets in Bangladesh

New Delhi. What started as a protest against a quota system for government jobs in Bangladesh has turned into widespread looting and rioting across the country, with the minority community, mainly Hindus, coming under attack. With Sheikh Hasina fleeing to India and an interim government still to be formed, videos of temples being set on fire and houses and businesses of Hindus being attacked have flooded social media.However, at the same time, there have been visuals of Bangladesh's Muslim clerics guarding a Hindu temple in Cumilla.

A report in Bangladesh's Daily Star said houses and business establishments of Hindus were attacked by mobs and their valuables were also looted in at least 27 districts on Monday.

An ISKCON temple in Meherpur, located in Bangladesh's Khulna division, and a Kali temple were vandalised and set on fire."One of our ISKCON centres (rented) in Meherpur was burnt, including the deities of Lord Jagannath, Baladev, and Subhadra Devi. Three devotees who lived in the centre somehow managed to escape and survive," ISKCON spokesperson Yudhistir Govinda Das tweeted.Hindu councillor Haradhan Roy of the Rangpur City Corporation was also reportedly killed on Sunday in one of the deadliest days since the start of the protest. Another councillor, identified as Kajal Roy, was also reportedly lynched. Over 100 people died on Sunday as protesters called for Sheikh Hasina's resignation and clashed with the police.

The lynching of Haradhan Roy was brought to light by Sanjeev Sanyal, a member of the Economic Advisory Council of the Prime Minister. "As a Bengali Hindu and a descendant of refugees, find this particularly chilling," he tweeted.A video, shared by a Hindu activist in Bangladesh, shows a girl in distress pleading for help in Pirojpur district. Another video shows a temple in Navgraha Bari in Chittagong being burnt by a violent mob.

The Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council, in a post on X, has listed 54 attacks on temples, houses and establishments of the Hindu community. These include the Indira Gandhi Cultural Centre, which promotes cultural exchange between India and Bangladesh.The widespread attacks on Hindus in Bangladesh are the most severe since 2021, when protests broke out across the country following the visit of Prime Minister Narendra Modi. The violence saw numerous Hindu temples being attacked.

Presently, Hindus make up about 8 per cent of Bangladesh's population, or around 13.1 million people. In 1951, the share of Hindus in Bangladesh's population was 22 per cent. As per a report by the Hindu American Foundation, over 11 million Hindus fled Bangladesh due to religious persecution between 1964 and 2013.Monindra Kumar Nath, senior joint general secretary of Oikya Parishad, a Hindu outfit, said the Hindus were fearing more attacks."They (Hindus) are crying, saying they are being beaten up, and their houses and businesses are being looted. What is our fault? Is it our fault that we are citizens of the country?" Nath told the Daily Star."Where would we go if such attacks continue here? How can we console the members of the Hindu community?" he further said.

BENGAL WARNED OF INFLUX OF HINDU REFUGEES

With the ouster of Hasina, there is a prospect of the Bangladesh Nationalist Party (BNP) and Jamaat-e-Islami getting a strong foothold in the political sphere, prompting a possible influx of Hindu refugees.India shares a nearly 4,096 km long land and riverine border with Bangladesh.Leader of Opposition in West Bengal Suvendu Adhikari has already warned the Mamata Banerjee-led government of being prepared to give refuge to one crore Hindus from Bangladesh.If this situation doesn't come under control, mentally be prepared to give refuge to one crore Hindu refugees. If the situation is not controlled there, Jamaat and radicals will take control," Adhikari told reporters.BJP leader Sunil Deodhar took to X to stress that the safety of Hindus in Bangladesh should be the priority. "

Anger In Khyber Pass As Bulldozers Roll On

New Delhi: The demolition drive at Khyber Pass in north Delhi entered the second day on Monday, with the Land and Development Office (L&DO) asserting that the constructions in the locality were illegal because the land belonged to the defence ministry. The angry residents claimed that they hadn't been given sufficient notice and that they had unjustly been rendered homeless.

Rakesh Kumar, a 62-year-old whose house was demolished on Monday, expressed his disbelief at this sudden turn in his life. Kumar, who has been giving home tuitions to the children in the area for many years, said both his house and source of living were now gone. He is among the hundreds of residents of Khyber Pass in the Civil Lines area who are nw uncertain about their future.Kumar, who was carrying a plastic bag with him, claimed to have all documents about having lived in the locality for the past 70-odd years. "I have documents from the time when my father started living here in 1951. I was born here and have grown old here. I hadn't ever expected it to end like this."At the demolition site on Monday, one could see bulldozers dismantling the buildings that were once home to the distressed people, who stood guarding their household belongings retrieved from the wrecked houses stacked in the open.

Sitting close to her belongings, Sandhya voiced her concerns about her children's education as they were forced to miss their exams due to the demolition of their home. Residents and human rights activists are calling for compensation or rehabilitation to help the people affected by the demolition rebuild their lives.

"My husband is the only bread-earner in the family and we can barely make ends meet with his money. Now the roof is gone from above our heads. I can't even think of what our lives will be like now." Dabbing at moist eyes with her dupatta, Sandhya added, "If they wanted us to vacate the place, they should have just given us enough time and maybe not undertaken the demolitions in the monsoon season. Last night it rained heavily. My children were out in the open and have fallen sick."

IMD issues 'yellow' alert for light-to-moderate showers

New Delhi: After some areas receiving very light rain on Monday, the city may witness intense rain activity from Tuesday to Thursday. India Meteorological Department (IMD) has issued a 'yellow' alert for light to moderate showers for the period.Safdarjung, the city's base station, recorded 'trace' rainfall along with Palam and Lodhi Road between 8.30am and 5.30pm. Ayanagar logged 1.7mm and Najafgarh 0.5mm rainfall.The cloudy skies with cooler breezes caused the maximum temperature to dip to 33.4 degrees Celsius, one degree below normal and 2.6 degrees lower than Sunday's maximum. The relative humidity oscillated between 70% and 94%. The minimum temperature stood at 26 degrees Celsius, one degree below normal."The monsoon trough is expected to come close to Delhi-NCR along with other weather systems likely to cause rain for the next three days," said an official. IMD has predicted "scattered to fairly widespread rainfall over Uttar Pradesh, Punjab, Haryana-Chandigarh-Delhi during the week".

The Met department said light to moderate rain might cause minor traffic disruption on roads, increased chance of vehicle accidents, and water accumulation in low-lying areas and on roads. "Check for traffic congestion on your route before leaving for your destination and follow traffic advisories," its forecast bulletin stated.

IMD's data reveals that Safdarjung has received 114.1mm of rainfall so far in Aug, with 107.6mm recorded on Aug 1 during an intense spell of heavy rain. The long-period average rainfall for the entire Aug is 233.1mm. July ended on a rain deficit of 3% with 203.7mm rainfall as opposed to the normal 209.7mm.Meanwhile, the AQI improved to 58 in the lower end of the satisfactory category on Monday. Air Quality Early Warning System for Delhi said AQI was likely to stay in the same category till Aug 8. India to record above-normal rainfall in August and September: IMDIndia's Meteorological Department predicted above-average rainfall in August and September due to favorable La Nina conditions. Rainfall is expected.

'Cannot be a coincidence': 14 deaths in a month at Asha Kiran shelter home strange, says Delhi HC

NEW DELHI: Delhi High Court on Monday called the deaths of 14 inmates of a govt-run Asha Kiran shelter home in a month "strange" and sought a detailed report on it from the social welfare department and Delhi Jal Board.

"Just too many deaths in a short span of time. Fourteen deaths in just one month is a large number. It cannot be a coincidence. It is strange," the bench said about the shelter home for the mentally challenged. The bench of Justice Tushar Rao Gedela noted that nearly all the deceased suffered from tuberculosis.The court directed Delhi govt's secretary for social welfare, under whose department Asha Kiran operates, to visit and inspect the conditions of the facility in Rohini on Aug 6 and file a report, stressing the need for immediate "curative measures".

It questioned how tuberculosis was "rampant" in a shelter home, as could be seen from the cause of deaths. The court also directed Delhi Jal Board to test the quality of water as well as the condition of water and sewer pipelines. The DJB and the social welfare department secretary were asked to file reports. The court was responding to a PIL seeking its intervention.During the hearing, the govt's standing counsel Sameer Vashisht told the bench that out of the 14 deceased, one was a minor, and the "maximum" deaths happened in the hospital where they were being treated. He submitted that all the dead inmates unfortunately suffered from "severe and profound category of intellectual disability", had comorbidities, and were found in "precarious conditions" before they were brought to the shelter home. There is a team of doctors and nurses in the shelter home and the exact details with respect to the deaths would be known after post-mortem reports are received, he added.

President Droupadi Murmu Receives Fiji's Highest Civilian Award

Suva (Fiji): President Droupadi Murmu was on Tuesday conferred the Companion of the Order of Fiji, the country's highest civilian award, as she hailed the ties between the two countries and said India stands ready to partner with Fiji to build a stronger, resilient, and more prosperous nation."President Ratu Wiliame Maivalili Katonivere of Fiji conferred the Companion of the Order of Fiji upon President Droupadi Murmu. This is the highest civilian award of Fiji," the President's Office said in a post on X.

Murmu, who is on a two-day visit to Fiji, described the honour as "a reflection of the deep ties of friendship" between India and Fiji. This is the first visit by an Indian head of state to the archipelago nation.As India emerges strongly on the global stage, we stand ready to partner with Fiji, according to your priorities, to build a stronger, more resilient, and more prosperous nation. Let us come together to unlock the full potential in our partnership for the mutual benefit of people of both our beloved countries," she said while addressing the Parliament.She said that despite the vast difference in size, India and Fiji have much in common, including vibrant democracies. She recalled that almost 10 years ago, speaking in this same Hall, Prime Minister Narendra Modi had underlined some basic values that unite India and Fiji."These include, 'our democracy, the diversity of our societies, our creed that all human beings are equal, and our commitment to the liberty, dignity and rights of every individual'. These shared values are eternal, and shall continue to guide us ahead," she said.

"In my short time here, I can see that the rest of the world has so much to learn from Fiji. The gentle Fijian way of life, the deep-rooted respect for traditions and customs, and an open and multicultural environment make Fiji so special in an increasingly conflict-ridden world. No wonder, Fiji is the place where the rest of the world comes to find its happiness," she said.She said she was confident that the newly announced projects, including the Super Specialty Cardiology Hospital to be established in Suva, would help to meet the priority needs of the people of Fiji and the wider Pacific region.he also said that it is heartening to know how the "Girmitiyas" and their descendants have been embraced by Fii when they first arrived here."More than 145 years ago, destiny bound our two countries together when 'Indentured' workers first arrived on the shores of Fiji Islands from India," she said.

Supreme Court upholds LG's right to appoint MCD aldermen: Who are aldermen?

NEW DELHI: The Supreme Court of India has upheld the Delhi lieutenant governor's (LG) authority to appoint Municipal Corporation of Delhi (MCD) aldermen, leading to varied reactions from the Aam Aadmi Party (AAP) and the Bharatiya Janata Party (BJP). The verdict, delivered nearly 15 months after the Delhi government filed its plea, favors the BJP in the 18-member standing committee. AAP expressed strong disagreement, calling it a hit on democracy, while the BJP defended the established practice.

In its ruling, a bench comprising Chief Justice of India (CJI) D Y Chandrachud and Justices P S Narasimha and J B Pardiwala dismissed the Delhi government's argument that the LG should act on the advice of the council of ministers when nominating 10 aldermen to the MCD. This decision has major implications for the composition of the MCD standing committee, the highest decision-making body in the municipal corporation.Following the December 2022 MCD elections, in which AAP ended the BJP's 15-year rule by winning 134 seats compared to BJP's 104 and Congress's nine, the MCD standing committee's formation has faced delays due to court proceedings.

In 2023, the MCD House voted to allocate three standing committee seats each to AAP and BJP. There was contestation over the fourth member, representing the BJP, and the subsequent appointment of aldermen led to disruptions in the House as opposition councillors clashed.

With the Supreme Court's ruling, the MCD will now conduct fresh elections to elect the crucial fourth member of the standing committee. Whether the previous 3-3 result holds will depend on the new elections.

If the ten nominated aldermen support BJP councillors in the zonal elections, the BJP may very well be able to turn the tide in its favour.Congress, which has only nine councillors, can play a crucial role in electing members of the committee at zonal level where ten aldermen can vote.

Can Minor Muslim Girls Marry After Attaining Puberty?: Centre Seeks Supreme Court's Priority Adjudication

New Delhi. The Centre on Tuesday urged the Supreme Court to adjudicate on priority as to whether a minor Muslim girl can marry a person of her choice after attaining puberty. Solicitor General (SG) Tushar Mehta, the second-highest law officer of the Centre, mentioned before CJI D.Y. Chandrachud a plea filed by the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) against the Punjab and Haryana High Court order, which had held that a Muslim girl can marry a person of her choice after attaining the age of 15.SG Mehta submitted that diverse views were being taken by different High Courts across the country, resulting in the filing of multiple special leave petitions before the apex court around the same issue. "Please see if this can be listed on priority," he said. At this, CJI Chandrachud assured SG Mehta that he would direct the listing of the batch of petitions.

In January last year, the top court issued notice to the government and others on NCPCR's plea to decide upon the question of law, clarifying that its decision not to stay the impugned order of the Punjab and Haryana High Court may not be used as precedent. It appointed senior advocate Rajshekhar Rao as amicus curiae in the matter to assist the court.

The SC pointed out that if the high court judgment -- which held that a Muslim girl aged 15 years can enter into a legal and valid marriage as per personal law -- was stayed, the girl might be restored to her parents against her wishes. Before the apex court, SG Mehta had contended that Muslim girls who were 14, 15, and 16 years old were getting married. "Can there be a defence of personal law? Can you plead custom or personal law as a defence against a criminal offence?" he saidThe plea filed by NCPCR said the Punjab and Haryana HC erred in ignoring the fact that sexual intercourse with a minor girl below the age of 18 years, is sexual assault as per the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act and this legal position cannot be changed due to marital status of the child and that whether on the facts and in the circumstances of the case and in law. It added, "The high court was justified in upholding that a minor girl, after attaining puberty after the age of 15, on her own willingness and consent, can enter into a marriage of her own choice while not considering the validity of a marriage with a minor all the while glossing over the fact that the impugned judgment would lead to endorsing child marriage which is illegal in India because POCSO Act applies to everyone."The high court's order came on a habeas corpus petition filed by a 26-year-old man against the detention of his 16-year-old wife in a children's home in Panchkula. The high court noted that such a marriage would not be void in terms of Section 12 of the Prohibition of Child Marriage Act 2006.

NEWS BOX

Tunisian court sentences 4 presidential hopefuls to jail, bars them from polls

Tunis. A Tunisian court on Monday sentenced four potential presidential election candidates to eight months in prison and banned them from running for office on a charge of vote buying, politicians and a lawyer told Reuters, a move they said was aimed at excluding serious competitors of President Kais Saied.The ruling reinforces the fears of opposition parties, candidates and human rights groups who have accused authorities of using arbitrary restrictions and intimidation in order to ensure the reelection of Saied in a vote set for Oct. 6.The decision was issued against prominent politician Abdel Latif Mekki, activist Nizar Chaari, Judge Mourad Massoudi and another candidate, Adel Dou, said lawyer Mokthar Jmai.Ahmed Nafatti, the manager of Mekki's campaign, said they still planned to submit his candidacy papers on Tuesday."The decision is unfair and unjust, and aims to exclude a serious player from the race," Nafatti said."It is a shocking rule, it aims to keep us away from running for the race after a series of restrictions," Chaari told Reuters.Another court late on Monday sentenced Abir Moussi, also a prominent opponent of Saied, to two years in prison, on a charge of insulting the election commission, local Mosaique radio reported.Last month, a court sentenced Lotfi Mraihi, a potential presidential election candidate and fierce critic of Saied, to eight months in prison on a charge of vote buying. It also banned him from running in presidential elections.

Elected in 2019, Saied dissolved parliament in 2021 and began ruling by decree in a move the opposition described as a coup. He has said he will not hand over power to what he calls "non-patriots."Opposition parties, many of whose leaders are in prison, have accused Saied's government of exerting pressure on the judiciary to crack down on his rivals in the 2024 elections and pave the way for him to win a second term.Saied has denied placing any restrictions on rivals.

"There are no restrictions on potential candidates for the presidential elections... this is nonsense and lies," Saied told reporters on Monday after submitting his official candidacy file.

Indonesian man, 45, kills neighbour who kept asking him why he wasn't married

World. A man in Indonesia allegedly killed his neighbour after he was upset and annoyed by the latter constantly asking him why he was not married, The Straits Times reported.The incident happened on July 29 in South Tapanuli regency, located in North Sumatra. Parlindungan Siregar, 45, went to the home of Asgim Irianto, a 60-year-old retired civil servant, at about 8 pm and started attacking him with a piece of wood without any warning.Local media, citing Assistant Police Commissioner Maria Marpaung, reported that the details of the attack were based on a statement by Asgim Irianto's wife.

The 60-year-old barged out of his house and into the street after the sudden attack, but he was chased by Parlindungan Siregar - who struck a heavy blow to the victim's head. After Asgim Irianto's fell to the ground, the 45-year-old allegedly beat his neighbour to death.

Residents in the neighbourhood jumped in and eventually stopped the attack before rushing Asgim Irianto to the hospital. However, the 60-year-old died on the way, Assistant Police Commissioner Maria Marpaung said.Parlindungan Siregar was arrested within an hour of the attack, local media reported. During questioning, he told the police that he was determined to beat Asgim Irianto to death because he was hurt by how often the 60-year-old would quip and ask why he was not married.Prior to the attack, the two reportedly also had arguments when the chickens they separately owned went to the other's coop, local media reported.

US Supreme Court rejects bid to lift Trump's gag order in hush money case

Washington. The Supreme Court on Monday shut down a long-shot push from Missouri to remove a gag order in former President Donald Trump's hush-money case and delay his sentencing in New York.The Missouri attorney general went to the high court with the unusual request to sue New York after the justices granted Trump broad immunity from prosecution in a separate case filed in Washington.The order states that Justices Clarence Thomas and Samuel Alito would have allowed Republican Andrew Bailey to file the suit, though not grant his push to quickly lift the gag order and delay sentencing.Bailey argued the New York gag order, which Missouri wanted stayed until after the election, wrongly limits what the GOP presidential nominee can say on the campaign trail around the country, and Trump's eventual sentence could affect his ability to trave."The actions by New York have created constitutional harms that threaten to infringe the rights of Missouri's voters and electors," he wrote.Bailey railed against the charges as politically motivated as he framed the issue as a conflict between two states. While the Supreme Court typically hears appeals, it can act as a trial court in state conflicts. Those disputes, though, typically deal with shared borders or rivers that cross state lines.New York, meanwhile, said the limited gag order does allow Trump to talk about the issues important to voters, and the sentence may not affect his movement at all. Democratic New York Attorney General Letitia James argued that appeals are moving through state courts and there's no state-on-state conflict that would allow the Supreme Court to weigh in at this point."Allowing Missouri to file this suit for such relief against New York would permit an extraordinary and dangerous end-run around former President Trump's ongoing state court proceedings," she wrote.Trump is under a gag order imposed at trial after prosecutors raised concerns about Trump's habit of attacking people involved in his cases.

Exiled author Taslima Nasreen's barb at Sheikh Hasina after flight from Bangladesh

Exiled Bangladeshi author Taslima Nasreen accused Sheikh Hasina of allowing Islamist groups to grow and enabling corruption, which she claims ultimately led to the former Prime Minister's downfall.

World Exiled Bangladeshi author Taslima Nasreen pointed to the ironic twist in Sheikh Hasina's resignation as Bangladesh Prime Minister and flight from the country after weeks of violent anti-government protests.An outspoken critic of religious fundamentalism, Nasreen accused Hasina of pandering to Islamists. She claimed that the same Islamists who forced her exile were now part of the student-led agitation that drove Hasina out of Bangladesh.In a post on X, Nasreen said, "Hasina in order to please Islamists threw me out of my country in 1999 after I entered Bangladesh to see my mother in her deathbed and never allowed me to enter the country again. The same Islamists have been in the student movement who forced Hasina to leave the country today."Nasreen was forced to leave Bangladesh in 1994 due to death threats from fundamentalist groups over her best-selling book 'Lajja', which was banned in the country. She has been living in exile since then.Hasina's resignation and escape from Bangladesh came amid violent student-led protests that have killed over 300 people. The protests began as a response to quotas reserving government jobs for families of veterans of the country's 1971 war of independence from Pakistan. The protests escalated into a campaign demanding Hasina's overthrow, which was met with a violent crackdown.Nasreen blamed Hasina for the situation, alleging that she allowed Islamist groups to flourish and turned a blind eye to corruption, which ultimately led to her downfall."Hasina had to resign and leave the country. She was responsible for her situation. She made Islamists to grow. She allowed her people to involve in corruption. Now Bangladesh must not become like Pakistan. Army must not rule. Political parties should bring democracy & secularism (sic)," she wrote.

Sheikh Hasina, 76, fled the country in a military aircraft and landed at the Hindon airbase near Delhi, where she was met by India's National Security Adviser Ajit Doval.Shortly after her departure, Bangladesh's army chief General Waker-Uz-Zaman announced Hasina's resignation in a televised address and said an interim government would be formed.

The chaos following Hasina's exit resulted in hundreds of protesters breaking into her official residence in Dhaka, expressing their frustration with her 15-year rule by looting, vandalising and running amok.

Kamala Harris officially secures Democratic presidential nomination: Report

World US Vice President Kamala Harris formally secured the Democratic Party's presidential nomination on Monday, becoming the first woman of colour to lead a majority party ticket in the November elections, The Associated Press reported.The nomination of Harris, 59, who became the first female Vice President in America's history in the 2020 elections, became official after a five-day online voting by the Democratic National Convention delegates concluded on Monday night.On July 2, Democratic National Committee Chair Jaime Harrison said that Kamala Harris had secured adequate Democratic delegate votes to become the party's nominee for president.The US Vice President also acknowledged the same on X, saying she was "honoured" to be the Democratic nominee for the November presidential elections.

"I will officially accept the nomination next week. This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are," she tweeted.Kamala Harris began her presidential campaign in a frenzy following the surprising exit from the White House race by US President Joe Biden, who endorsed her for the top job. The 81-year-old President had been facing severe pressure to drop out of the presidential race after a dismal debate performance against Donald Trump in June. Kamala Harris and her team, however, worked rapidly to secure the backing of as many as 1,976 Democratic delegates - needed to officially clinch the nomination.According to a survey by The Associated Press, the 59-year-old US Vice President locked down the necessary commitments a mere 32 hours after Biden's announcement.

Though the online nomination by delegates was held remotely, the Democratic National Convention said that a ceremonial roll call would be held at the event, set to be kicked off on August 19 in Chicago.Meanwhile, the mystery over Kamala Harris's running mate deepens ahead of her announcement of the selection on Tuesday. According to news agency Reuters, she has narrowed down to two finalists - both Governors - Tim Walz of Minnesota and Josh Shapiro of Pennsylvania.She is slated to appear for the first time with her running mate at a public event at the Temple University in Philadelphia on Tuesday.

Tropical storm Debby blows cocaine worth $1 million onto Florida beach

World Over $1 million (nearly Rs 9 crore) worth of cocaine washed up on a beach in Florida after tropical storm Debby hammered the state with torrential rain and strong winds.After making landfall as a Category 1 hurricane early on Monday morning, it carried more than two dozen 70-pound packages of cocaine ashore as winds exceeded 80 miles (288 km/hour) per hour, the New York Post reported, citing the US Border Patrol.Taking to X, US Border Patrol Acting Chief Samuel Briggs II shared pictures of the cocaine packages, which it said were discovered by a citizen who then informed the authorities."Hurricane Debby blew 25 packages of cocaine (70 lbs) onto a beach in the Florida Keys. Good Samaritan discovered the drugs & contacted authorities. US Border

Patrol seized the drugs, which have a street value of over $1 million dollars," Briggs tweeted.The packages carried a glowing red triangular symbol on them.The citizen discovered the drugs - concealed in a garbage bag - among seaweed, leaves and other scraps that washed up on the beach.This is not the first time that cocaine and other drug packages washed up ashore on southern Florida beaches. In June, a beachgoer in search of sea turtle nests at a north Florida beach stumbled upon $4 million worth of cocaine bricks, New York Post reported.Debby, meanwhile, battered the state on Monday, leading to at least four deaths, including a 13-year-old boy who was crushed after a tree fell on his family's mobile home. Several homes were flooded, prompting the rescue of hundreds. Record rain caused flash flooding with up to 76 centimetres possible in some regions, the National Hurricane Center said, The Associated Press reported.It has since been downgraded from a hurricane to a tropical storm, and turned its direction towards Georgia.

Nepal tightens security along India border in wake of Bangladesh unrest

Nepal has ramped up security measures along its border with India after the ouster of Bangladesh PM Sheikh Hasina, fearing potential infiltration. The Ministry of Home Affairs has issued directives to security personnel to remain vigilant and prevent unauthorised entries.

Kathmandu Nepal on Monday stepped up security at its border with India following ouster of Prime Minister Sheikh Hasina in Bangladesh, fearing a potential infiltration of citizen from the violence-hit country.The Ministry of Home Affairs instructed security agencies to adopt high alertness along the border to prevent unauthorised entry through international border areas, police said.According to the police, the Home Ministry directed the security personnel deployed for border security to take extra precautions to prevent such infiltration.All security personnel deployed in the border areas have been instructed through circulars to closely monitor and take measures against potential illegal entries and activities from third countries," said a senior official.They have been instructed to remain high on alert from Kakarbhitta in the East to Lumbini in the West, the official said.In the past, groups of Rohingyas illegally entered Nepal via the Mechi Bridge and other entry points, finally reaching Kathmandu following a military takeover in Myanmar.Bangladesh descended into chaos as Prime Minister Hasina surreptitiously resigned and fled the country in a military aircraft while the army stepped in to fill the power vacuum.

As the news of Hasina's departure spread, hundreds broke into her residence, vandalising and looting the interiors, providing dramatic expression to the anti-government protests that have killed more than 300 people in a fortnight.

Violent UK protesters will face 'full force of the law', says PM Keir Starmer

Following the fatal stabbing of three girls in Southport, anti-immigrant and anti-Muslim protests have erupted across the UK. PM Keir Starmer assures that those involved in violence will face severe legal consequences.

London British Prime Minister Keir Starmer said violent protesters who had targeted Muslim communities would swiftly face the "full force of the law" as he sought to quell days of anti-immigration rioting.

The fatal stabbing of three young girls in the northwest English town of Southport last week has been seized on by anti-immigrant and anti-Muslim groups, with disinformation spread online and amplified by high-profile far-right figures to spark disorder in towns and cities."Whatever the apparent motivation, this is not protest, it is pure violence and we will not tolerate attacks on mosques or our Muslim communities," Starmer said on Monday after an emergency meeting with police and prison chiefs."The full force of law will be visited on all those who are identified as having taken part."

Police chiefs said they had arrested 378 people since the start of the unrest and warned of "lengthy prison terms" for those found guilty of violent disorder.

The violence erupted last Tuesday after social media posts said the suspected attacker in Southport was a radical Islamist who had just arrived in Britain and was known to intelligence services.

Police say the 17-year-old suspect was born in Britain and they are not treating it as a terrorist incident. The suspect's parents had moved to Britain from Rwanda.Interior minister Yvette Cooper said rioters had felt "emboldened ... to stir up racial hatred" and that the protests were not a proportionate response to concerns about near-record levels of immigration."Reasonable people ... do not pick up bricks and throw them at the police," she said.Protests, mostly involving a few hundred people, have continued across the country, with shops looted and mosques and Asian-owned businesses attacked. Cars have been set on fire and some unverified videos on social media have shown ethnic minorities being beaten up.Australia and Nigeria were among countries to issue warnings on Monday to citizens resident in or travelling to Britain.On Monday evening, protests spread to Plymouth in southwest England. Several hundred anti-immigration protesters wearing English and British flags faced off against a greater number of counter-protesters, kept apart by police in riot gear.

Protesters threw bricks and fireworks and scuffled with police. Sky News said three police officers were injured.In Rotherham, northern England, protesters on Sunday tried to break into a hotel that housed asylum seekers in what Starmer called an act of "far-right thuggery", following protests on Saturday in other English cities and in Belfast.Starmer said a "standing army" of specialist police officers would tackle outbreaks of violence where needed.Northern Ireland's assembly will end its summer break a day early to discuss the violence.

POLICE BLAME ONLINE DISINFORMATION

Police have blamed online disinformation, amplified by high-profile figures for driving the violence.

Stephen Yaxley-Lennon, known by the pseudonym Tommy Robinson and previously the leader of the defunct anti-Islam English Defence League, has been blamed by media for spreading misinformation to his 875,000 followers on X.They are lying to you all," Yaxley-Lennon said. "Attempting to turn the nation against me. I need you, you are my voice."Elon Musk, the owner of X, also weighed in. Responding to a post on X that blamed mass migration and open borders for the disorder in Britain, he wrote: "Civil war is inevitable.

NEWS BOX

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: Kishore Jena says Javelin rivalry is 'friendly'

New Delhi. Indian javelin thrower Kishore Jena has commented on the famous rivalry between Neeraj Chopra and Arshad Nadeem and claimed that everything is friendly between the two ahead of the qualifying round on Tuesday, August 6. Neeraj vs Nadeem is one of the battles that fans are expecting to watch in the men's javelin event at the Paris Olympics as both men have pushed each other to the limit in recent times.

The rivalry between Neeraj and Arshad intensified when they finished one-two in the javelin throw at the World Championships in August 2023. However, fans were robbed of seeing the opportunity to see the Indian and Pakistani javelin stars go head to head at the Asian Games as Nadeem had to pull out of the event due to injury. Now, both men are expected to reignite their rivalry on the big stage of the Olympics and Jena weighed in on it.

Speaking to ANI, the Indian javelin thrower said that Neeraj and Nadeem have a good friendship outside of the field and there is no

animosity."No, it's not like that. Since it's the Olympics, a lot of countries have come. We don't think like that. There is nothing like that. It is friendly when we meet them. I also meet them. There is no such intention," said Jena.

Everyone has high hopes for Neeraj

Jena was to quick praise Neeraj before his title defence and said that Indian athletics had grown a lot because of him. Jena said that everyone has high hopes for Neeraj and it feels good to have him around others.

"You know how much Indian athletics has grown because of Neeraj bhai. Everyone has high hopes for him. It feels good that he is with us. He is staying with us. We wish him well," said Jena.Jena commented about his preparations and vowed he would produce his best in the qualifying round on Tuesday.

"Preparation is very good, and we are getting a lot of support from here. It will be good. I will give my best tomorrow. I will play like a finalist. It is my first time, so l will give 100 per cent," said Jena.The javelin qualifying round will be one of the events starting things off for the Indian contingent on Tuesday, with Jena being in Group A and Neeraj in Group B.

Paris Olympics 2024: Mondo Duplantis imitates Yusuf Dikec, shooter reacts

Sweden Pole Vault great Mondo Duplantis decided to imitate Yusuf Dikec after his historic gold medal at the Paris Olympics 2024 on August 5, Monday. This would prompt the shooting sensation to respond to Duplantis' imitation with a tweet. Duplantis was in top form on Monday as he shattered his own benchmark to make a new world record in Paris, stunning the crowd in attendance.The Swede would then decide to celebrate his win in a special fashion as he posed like Dikec, who had become an overnight sensation for shooting at the Olympics without any gear. Dikec would end up getting the silver medal in the 10m air pistol mixed team event.The imitation from Duplantis certainly impressed Dikec, who responded with a simple congratulatory

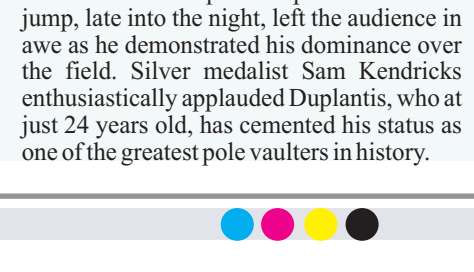

message to the Swedish star. The Turkey shooter also posted a picture of Duplantis imitating him in the tweet as well.

How did Duplantis perform at Olympics 2024?

Duplantis became only the second pole vaulter in history to defend his title, doing so with remarkable ease. He needed only four successful attempts to secure the gold with a height of 6.00 meters, before setting a new Olympic record at 6.10 meters. He then astonishingly raised the bar to 6.25 meters, breaking his own world record of 6.24 meters, set earlier in 2024 at the Wanda Diamond League.

Duplantis began his competition at 5.70 meters, clearing it by about a meter. He skipped 5.80 meters and effortlessly soared over 5.85 meters, as competitors around him started to falter.Clearing 6.00 meters, a dream target for most vaulters, appeared to be a mere warm-up for Duplantis. His final jump, late into the night, left the audience in awe as he demonstrated his dominance over the field. Silver medalist Sam Kendricks enthusiastically applauded Duplantis, who at just 24 years old, has cemented his status as one of the greatest pole vaulters in history.

India pins hopes on hockey, wrestling, javelin stars in Paris showdown

☛After a heartbreaking Monday, three big names (two individual and one team) will be in action on Tuesday — the men's hockey team (semifinal against Germany), Vinesh Phogat (in the women's 50kg in wrestling) and Neeraj Chopra (in the men's javelin).

PARIS. After a heartbreaking Monday, three big names (two individual and one team) will be in action on Tuesday — the men's hockey team (semifinal against Germany), Vinesh Phogat (in the women's 50kg in wrestling) and Neeraj Chopra (in the men's javelin). It's two to three very different stars, too. Vinesh was the public face of the protest by Indian wrestlers in 2023. Lots of Indians have a soft spot for hockey. And, lastly, Chopra is leading the revolution in Indian athletics, the man who will be defending gold.When the Indian XI walk out on to the Paris turf, it would be with a lot of hope. The inspirational display against Great Britain with 10 men should give them some belief. Harmanpreet Singh, who has led this team with under-stated efficiency at the back (while defending) and from the front (while scoring from penalty corners) will again be key, especially in the absence of the suspenses Amit Rohidas. Manpreet Singh's role while defending penalty corners will be even more outsized without Rohidas, one of the world's best first rushers. At the back, the inspirational PR Sreejesh will look to bring out his A game again. Forward Abhishek, who has come of age in this tournament, will also have to tuck away half-chances against the world champions.

India may have a positive recent memory against Germany — they beat them in the bronze-medal playoff in 2021 — but this is a different, more robust Germany.

Moving on from hockey to javelin, the mood in his camp is relaxed. The eagle will fly through the Paris sky in the qualification round on Tuesday afternoon. There is no other Indian athlete who's followed as closely as the javelin ace. The young man from Panipat has turned into a global icon. For India, he has already transcended sport. He is joy, celebration, victory all seamlessly morphed into hope for billion plus people. It

will be at the cavernous Stade de France, the country's symbol of sporting supremacy. Understandably, the stadium is home for France football and rugby teams. On Tuesday, it will be the stage for India's only world and Olympic champion in athletics.

The stadium rises as a behemoth as one approaches the parapet leading up to the gates. The purple Mondo track stares at you. It is fast but may not aide javelin throwers as much as it would sprinters. When Neeraj walks on to the ground for the qualification, the entire nation would have their eyes transfixed on the TV screens. Neeraj is in Group B with 15 other throwers. The field for the World No 2 javelin thrower is quite simple. Three names would stand out. Former world champion Anderson Peters (season's best: 86.62m) is clubbed with him. Pakistan's Arshad Nadeem (84.21m) is also with him. His personal best is 90.18 at the Birmingham Commonwealth Games. Up and coming star, Max Dahning, too figures on the list and is the only one to cross the 90m mark this season.Neeraj has not competed in a major competition since the Paavo Nurmi Games where he managed 85.97m. He skipped Ostrava Golden Spike before this as a precaution. He did not participate in the Paris Diamond in the first week of July because he felt it was not needed. Until now he had two big international competitions – Doha Diamond League and the above-mentioned Paavo Nurmi. Neeraj's nemesis, Yakub Vadlejch of Czechia, is cin the Group A. Out of all the athletes, Vadlejch is the second best thrower in 2024.Of course, as long as Neeraj throws 84m in the qualification, he will advance to the final. And considering he usually throws 84m at the first time of asking, it could be 'one and done'.

Lovlina Borgohain vows to come back 'stronger than ever' after Olympics failure

Paris Olympics 2024: Lovlina Borgohain was disappointed after she failed to win a medal, but she also pledged to make a strong comeback. She lost to China's Li Qian in the quarterfinal

New Delhi. Lovlina Borgohain dropped a note on her social media handles where she pledged to make a strong comeback after her disappointing campaign in Paris Olympics 2024. Back in 2021, Lovlina became only the third Indian boxer after Vijender Singh and Mary Kom to win a boxing medal for India in the quadrennial event.But this time around, Lovlina could not quite step up. However, instead of throwing in the towel, the 26-year-old said that she would be looking for a fresh start and try and return "stronger than ever".

'This is not over'

"I really want to say sorry to the entire Nation that I couldn't bring a medal home this time. Especially to the people of Assam who always pray for me no matter what. I will work harder and come back stronger than ever next time. This isn't over, looking for a fresh start once again," Lovlina wrote.

Paris Olympics 2024: India Schedule | Full Coverage | Medal Tally

Lovlina also thanked his coaches, support staff and the others, who helped her out in her journey to the Paris Olympics."I also want to thank all the coaches, support staff, SAI, Assam Government, BFI, Reliance Sports Foundation, IOS sports and all my sponsors for all the support and encouragement they showered on me," Lovlina added.

Lovlina Borgohain's performance in Paris 2024

Lovlina began her campaign with a stunning victory over Sunniva Hofstad from Norway. With the victory, she was only one win short of securing another medal in the showpiece. But that was not the case as China's Li Qian defeated her.Had Lovlina won her quarterfinal bout, she would have joined PV Sindhu and Manu Bhaker in the elite list of Indian women with multiple medals in the Olympics. It now remains to be seen of Lovlina returns four years later for the Los Angeles Olympics.

Paris Olympics: Noah Lyles sprint double bid continues, eases through 200m heat

New Delhi. Less than 24 hours after clinching gold in the 100 meters, Noah Lyles continued his pursuit of the prestigious Olympic sprint double by effortlessly advancing through his 200m heat on Monday with a time of 20.19 seconds. The American sprinter, who excels in the 200m, remains unbeaten in 25 races over this distance since earning bronze at the Tokyo Olympics in 2021. Lyles has also secured the last three world titles in the event.

advertisement

Lyles aims to achieve an ambitious goal of winning four gold medals in Paris, targeting the 100m, 200m, 4x100m relay, and possibly the 4x400m relay. Such a feat would place him alongside legendary compatriots Jesse Owens and Carl Lewis, who each won four golds in a

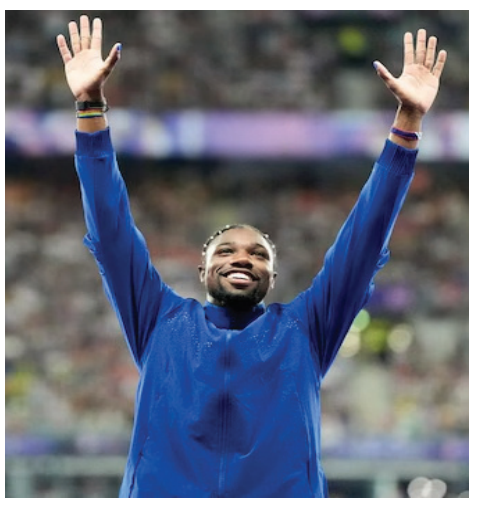

single Games, though their fourth medals came in the long jump rather than the longer relay."It feels good to be out here," Lyles told reporters. "It was in my head win the 120, win the 150, check around, win the heat."

Defending champion Andre de Grasse of Canada, the last sprinter to beat Lyles, followed closely behind, finishing in 20.30 seconds. American Kenny Bednarek, who secured silver ahead of Lyles in Tokyo and was runner-up to him at the 2022 World Championships, posted the fastest time of the heats with 19.96 seconds despite easing up before the finish. Bednarek also competed in Sunday's 100m final, where his time of 9.88 seconds placed him seventh.Erriyon Knighton, who has previously won world championship silver and bronze medals as a teenager, ensured a strong American presence in the semi-finals by winning his heat in 19.99 seconds, the only other sub-20 time of the evening. Now 20, Knighton is eager to make his mark on the Olympic stage after years of being touted as the next big star.

Nick Hockley to step down as Cricket Australia CEO after 5-year stint

☛Nick Hockley announced that he would step down as the CEO of Cricket Australia after serving them for five years. He is expected to leave his role around the end of March.

New Delhi. Cricket Australia (CA) CEO Nick Hockley ha to step down by the end of the next cricket season, after an illustrious career spanning nearly 13 years in Australian cricket. Hockley, who has served as CA CEO for five of those years, is anticipated to leave his role around the end of March 2025, or later, subject to the appointment process of his successor.

advertisement

Hockley first took up the position of interim CEO in June 2020, before being confirmed as the permanent CEO eleven months later. His tenure has been marked by his adept management through the turbulent period of the COVID-19 pandemic.Under his leadership, CA has laid strong foundations for growth, including rolling out a comprehensive five-year strategy and securing significant media deals with Seven West Media, Foxtel Group, and Disney Star in India.Notably, a new player Memorandum of Understanding (MOU) with the Australian Cricketers' Association was established, featuring a substantial 66% pay increase for female professional cricketers. Additionally, the Big Bash league has been rejuvenated under his

guidance."This was a difficult decision, however following what promises to be a blockbuster summer and with our five-year strategic plan well progressed, this is the right time to pursue another challenge, while giving the Board plenty of time to find its next CEO to build on the strong foundations now in place," Hockley said in a press conference."This is not the time for goodbyes, as I remain completely focussed on the season ahead and supporting the Board on succession and a smooth transition."

Nick Hockley's journey as Australia cricket CEO

On the international stage, Hockley has overseen an extraordinary era of success for Australia's national cricket teams. Highlights include Australia's first tour to Pakistan in over two decades, winning and retaining both the women's and men's Ashes, and clinching six ICC trophies, such as the men's and women's Cricket World Cups (2022 and 2023), the men's and women's T20 World Cups (2021 and 2023), the World Test Championship in 2023, and the Men's Under-19 Cricket World Cup in 2024. Moreover, Australia secured gold at the Commonwealth Games in 2022.

Hockley joined Australian Cricket in October 2012 as the General Manager of Commercial & Marketing for the ICC Cricket World Cup 2015, which saw over a million attendees and generated a significant economic impact.

Following a short period as Head of Commercial Projects, Hockley was named CEO of the Local Organising Committee for the ICC T20 World Cup 2020, achieving record-breaking success at the Women's T20 World Cup with a historic final at the MCG.

Olympics 2024: France overcome Egypt 3-1 to setup football final with Spain

☛Jean-Philippe Mateta was the star of the show as his brace helped France reach the football final of the Olympics for the first time in 40 years. France will now face Spain in the final on Friday, August 9.

New Delhi. France will compete in the Olympic men's football final for the first time in 40 years after a thrilling 3-1 victory over Egypt in extra time at Lyon's stadium on Monday. They will face Spain for the gold medal. The match saw France come from behind after Egypt's Mahmoud Saber scored a spectacular goal, marking the first time France had conceded in the tournament. Jean-Philippe Mateta equalized with a late strike, pushing the game into extra time.

advertisement

Mateta then scored his second goal of the match, followed by Michael Olise, who sealed the victory in extra time. This win propels Thierry Henry's team into Friday's final at Parc des Princes against Spain, who defeated Morocco 2-1 earlier. Egypt, in their third Olympic semi-final, had more goal attempts in the first half and took the lead in the 62nd minute when Saber scored on a

rebound. Despite hitting the woodwork three times, France equalized seven minutes from time when Mateta netted from an Olise pass.

The match took a decisive turn in extra time when Egypt's Omar Fayed received a second yellow card for a foul on Desire Doue, reducing Egypt to 10 men. Mateta's towering header in the 99th minute put France ahead, and Olise added another goal three minutes into the second half of extra time, ensuring France's place in the final.Egypt will now compete for the bronze medal against Morocco in Nantes on Thursday. Earlier on in the day, Spain had reached the final with a comeback win over Morocco.

The 2020 silver medallists found themselves trailing in the first half of the semi-final after Soufiane Rahimi, the tournament's top scorer, netted a penalty for his sixth goal of the Games. Barcelona's Fermin Lopez leveled the score midway through the second half in Marseille, capitalizing on a loose ball in the penalty area. Substitute Juanlu Sanchez secured the victory and his team's place in Friday's final in Paris by drilling home the winning goal five minutes from time.

Malaika Arora

Slips Into White Bralette And G-String, Takes A Dip In Pool On Maldives Vacay

Malaika Arora is turning up the heat now. Away from the frenetic pace and chaos of everyday life, the actress has escaped or a happy vacation in Maldives. She has been sharing happy photos and videos on her Instagram handle, keeping fans updated on her whereabouts. Having said that, she recently amped up the heat in a white bralette teamed with a G-String.She shared the photos, taking a dip inside the pool, which overlooked the azure blue waters of Maldives. Along with the pictures, she wrote, 'Salty n blue.'

Earlier, Malaika Arora shared a few snapshots from her Maldives getaway, on her Instagram stories. One photo featured a swing on the deck of her luxury resort, another showcased a relaxing spa corner, and a third captured her gazing out at the stunning blue ocean. Her hair was tied in a messy bun and she faced away from the camera.Malaika Arora and Arjun Kapoor fuelled breakup rumours as they noticeably ignored each other at a recent fashion event. In a video shared by paparazzo Viral Bhayani, the couple, who have been the subject of breakup speculations, were spotted sitting far apart. The video even showed Malaika walking past Arjun while he was taking a selfie with a fan. Although Arjun made a thoughtful gesture to protect her from the crowd by placing his hand behind her, Malaika didn't acknowledge him and continued walking without looking back, adding more weight to the breakup buzz.

Amid the ongoing rumours surrounding her "on-off relationship" with Arjun, Malaika recently spoke about how the internet can be a very toxic space."I have somehow built a mechanism — or shield, I would say — around me where I don't let the negativity through anymore," Malaika told Hello magazine. "I've insulated myself from it. Whether it's people, a work environment, social media or trolls. The minute I feel that energy, I recoil instantly. It's something I've learned to do over time. It would get to me earlier and I would lose sleep over it. I'd be lying if I said things don't affect me at all — I'm human too and so I will cry, break down and have all the emotions associated with being trolled. But you'll never see that in public."

Kriti Sanon

Wishes Kajol Happy Birthday With A BTS Photo From Do Patti Sets, Calls Her An 'Inspiration'

Kajol has turned a year older today and has been getting wishes from all corners. Today, many celebrities including Kareena Kapoor Khan wish her. Kriti Sanon also shared a BTS photo from Do Patti sets and wished her. Kriti also called Kajol an inspiration.Taking to her Instagram stories, Kriti shared a photo in which she is seen sharing a selfie with Kajol. "Happy Birthday, Kajol Maam! Working with you again has been an incredible experience and I cannot wait for people to see your magic in Do Patti. You're not just an amazing person but an inspiration to all of us. I hope this year brings you immense happiness and joy. Sending you lots of love and a big, warm hug! @kajol." Kareena posted a beautiful black and white picture of Kajol and said, "Happy birthday to the loveliest @kajol," accompanied by a red heart emoji.

The teaser of Do Patti has also been released. The teaser opens with an aerial view of Manali and Kajol is seen as a cop riding a bike. Her voice can be heard in the background throughout the video. She is talking about wrong and right situations in life. Kriti Sanon's character is also shown as a glamorous one. She is seen in a grey shade. Looks like it is a murder mystery but still nothing is clear. The film will surely keep you on the edge of your seat.Last year, Kriti Sanon announced her first film as a producer. She took to her Instagram handle to share the first photo featuring her, Kajol along with others.Apart from this, Kajol will be soon seen in Maharagni – Queen of Queens,' with Prabhu Deva. This action-packed thriller marks the long-awaited reunion of these actors after nearly three decades since their collaboration in Rajiv Menon's 'Minsaara Kanavu' (1997). Steering this cinematic endeavor is director CharanTej Uppalapati. Recently, Ajay Devgn unveiled the teaser. The teaser highlights Kajol's dynamic character engaging in intense battles, displaying remarkable skills and flair. Alongside, the film boasts a stellar lineup including Naseeruddin Shah, Samyuktha Menon, Jisshu Sengupta, and Aditya Seal.

Riteish Deshmukh Shares Hilarious Birthday Video For Genelia: 'You Have Truly Changed My Life'

Genelia D'Souza and Riteish Deshmukh have always been a favourite among fans and the media. The Bollywood stars first met on the sets of their debut film Tujhe Meri Kasam in 2003 and quickly became close friends.Despite coming from different cultural backgrounds – Genelia being a Mangalorean Catholic and Riteish hailing from a prominent political family in Maharashtra – their friendship blossomed into love. In 2012, the couple tied the knot in a traditional Maharashtrian ceremony. ?

On Genelia's birthday today, hubby dearest Riteish took to Instagram to share a hilarious video with a sweet note. Sharing the video, "Happy Birthday Baiko @geneliad – you have truly changed my life." ?Not long back, Genelia made a comeback with the romantic-drama Ved, directed by Riteish himself. Even during her break from acting, Genelia continued to receive film offers. However, after she appeared in Ved, the number of calls tripled. ?

Genelia, during an interview with indianexpress.com, said, "Thankfully people were still calling me but it was few as many thought I had quit acting. Surprisingly, they all thought I left the industry because I got married to this family (Riteish is the son of former Maharashtra CM, late politician Vilasrao Deshmukh). For them, it was never about me. Riteish would often tell me that you don't want to work and because of you people are telling me".

She added, "Riteish said I was being negligent about something I love. Earlier, I would totally devote myself to film after film. Now, I am also in a state where my kids have grown up and are busy with their own things," she shared.eanwhile on the work front, Genelia D'Souza and Aamir Khan have begun filming for their Bollywood comeback film, Sitaare Zameen Par. Sitaare Zameen Par would mark Aamir's first Christmas release in eight years. He last released a film on Christmas in 2016, rolling out his blockbuster film Dangal.

Amitabh Bachchan Never Saw Aishwarya Rai as Daughter-In-Law, Says Jaya Bachchan In Viral Interview

Amitabh Bachchan and Aishwarya Rai shared a close bond even before she married his son, actor Abhishek Bachchan. The legendary star worked with the actress in a few films, including Mohabbatein and Hum Kisise Kum Nahin. So when Aishwarya got married into the family, Amitabh couldn't see her as a daughter-in-law. Instead, Jaya Bachchan once revealed, Big B welcomed her into the family as a daughter.Speaking with Karan Johar on Koffee With Karan, Jaya Bachchan said, "Whenever he sees her, he becomes happy. He never saw Aishwarya as a daughter-in-law. He always saw Aishwarya as a daughter. Amitji, the minute he sees her, it's like he's looking at Shweta coming home. His eyes light up. She'll fill the vacuum that Shweta left."

In another episode of the show, Abhishek praised the Bachchan ladies for making Aishwarya feel at home. "Yeah, I think credit has to be given entirely to the girls. I have very little to do with it. What works also is that Maa and her (Aishwarya) are very close. They talk about everything. When a woman first comes to her husband's house, she feels a bit out of place, evidently and obviously. I think the only person who can truly fill that void is her mother-in-law," he said.

Aishwarya married Abhishek in 2007. They welcomed their daughter Aaradhya Bachchan in 2011. While the couple has kept their relationship away from the spotlight, restricting their PDA to posts on each others' birthdays and their wedding anniversary, eyebrows raised when Aishwarya was recently seen posing alone on the red carpet at the Ambani wedding while Abhishek joined his family.Abhishek had everyone's attention when he 'liked' a post on divorce. Later, it was revealed that one of the writers of the post was Abhishek and Aishwarya's friend and the actor was only supporting his friend. Meanwhile, immediately after the Ambani wedding, Aishwarya flew out of Mumbai with her daughter.